Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 235
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
सोमवार, 01 सितम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 भाजपा शरद पवार पर हमलावर, सुप्रिया सुले ... 4 मोदी के चीन जाने से पहले ही ट्रंप ने ले लिया .. 7 बीसीसीआई को 450 करोड़ के स्पॉन्सरशिप ...

संक्षिप्त न्यूज

राहुल गांधी का बिहार में महत्व नहीं, तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट बनने पर भाजपा का कटाक्ष

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार के आरा में आयोजित 'मतदाता अधिकार यात्रा' की रैली के दौरान खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी नीतियों की नकल करने का आरोप लगाते हुए उन्हें 'नकलची मुख्यमंत्री' करार दिया।

इस घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तेजस्वी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का वहां (बिहार में) कोई महत्व नहीं है... वहीं, तेजस्वी यादव बिना किसी सलाह-मशविरा के घोषणाएं कर देते हैं। इससे पता चलता है कि उनका क्या महत्व है।'

तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा 'डरी हुई है' और उनके 'विजन को लागू करना चाहती है'। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ बाकी है, जिसका खुलासा वे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद करेंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा, 'बिहार में हर कोई कह रहा है कि हमें असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं।' उन्होंने कहा, 'हमने माता जानकी का आशीर्वाद लिया और हम सभी चाहते हैं कि बिहार का विकास हो।' अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने एक नारा भी दिया, 'धान की रोटी तवा में, विरोधी उड़ गये हवा में'।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ उनकी नीतियों की नकल कर रहे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं।

टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी बोले-

एक ही मंत्र 'वोकल फॉर लोकल', एक ही रास्ता 'आत्मनिर्भर भारत'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ से हुई तबाही पर दुख और पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 125वें एपिसोड में उन्होंने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर देशवासियों से वोकल फॉर लोकल की अपनी अपील दोहराई। उन्होंने टैरिफ का जिक्र किए बिना इशारों-इशारों में देशवासियों से इससे खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भरता को हथियार बनाने का आह्वान किया।

पीएम मोदी बोले- गर्व से कहो 'ये स्वदेशी है'

पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश-भर में 'गणेश उत्सव' की धूम

है। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। इन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रौशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो और भी ऐसा बहुत कुछ, जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो 'ये स्वदेशी है', गर्व से कहो 'ये स्वदेशी है'। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र 'वोकल फॉर लोकल', एक ही रास्ता 'आत्मनिर्भर भारत', एक ही लक्ष्य 'विकसित भारत'।'

'जहां स्वच्छता है, वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है'

उन्होंने कहा कि खुशियों के बीच आप सभी स्वच्छता पर जोर देते रहें, क्योंकि जहां स्वच्छता है, वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है। साथियों, 'मन की बात' के लिए मुझे इसी तरह बड़ी संख्या में अपने संदेश भेजते रहिए। आपका हर सुझाव इस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाते रहें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो और भी नए विषयों की चर्चा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

अमित शाह ने अहमदाबाद में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, पौधारोपण अभियान में भाग लिया

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां पौधारोपण अभियान में भाग लिया और शहरी स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के घाटलोदिया वार्ड में ''एक पेड़ मां के नाम'' पहल के तहत पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। यह अभियान लोगों को अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अमित शाह

यह कार्यक्रम अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा आयुष्मान वन में आयोजित किया गया। वहीं, एक अन्य कार्यक्रम में शाह ने अहमदाबाद के गोटा वार्ड में 3.84 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया।

इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि यह केंद्र आयुष्मान भारत के तहत पीएमजेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) कार्ड, आभा कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना के साथ-साथ अन्य सभी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

इसके अलावा, यह गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और महिलाओं के रोगों के निदान, उपचार सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करेगा।

विज्ञप्ति में कहा गया कि नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा जांच, निदान, उपचार सेवाएं तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

यह केंद्र सभी संचारी रोगों का शीघ्र निदान, उपचार और रेफरल, रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर समेत अन्य रोगों के लिए रोगियों की जांच और रेफरल जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा।

धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट की सुरंग भूस्खलन से बंद, 19 कर्मचारी फंसे

पिथौरागढ़ । उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे राष्ट्रीय जलविद्युत निगम के कम से कम 19 कर्मचारी पावर हाउस की सुरंगों में फंस गए हैं। यह घटना रविवार को हुई, जब भूस्खलन के कारण सामान्य और आपातकालीन दोनों सुरंगें अवरुद्ध हो गईं।

पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि सुरंग का प्रवेश द्वार बड़े-बड़े पत्थरों से बंद हो गया है। फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान तेजी से चल रहा है और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, फंसे हुए सभी कर्मचारी कंपनी और प्रशासन के संपर्क में हैं और उनके पास पर्याप्त भोजन सामग्री उपलब्ध है। धारचूला के उप-जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने जानकारी दी कि सीमा सड़क संगठन की जेसीबी मशीनों को भी काम में लगाया गया है और लगातार मलबा गिरने के बावजूद, शाम तक रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

'वाहन अगर सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उस पर टैक्स नहीं लगे'

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई वाहन सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में नहीं आता है, तो उसके मालिक पर उस अवधि के लिए मोटर वाहन कर का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिसंबर 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'मोटर वाहन कर प्रतिपूरक प्रकृति का होता है। मोटर वाहन कर लगाने का औचित्य यह है कि जो

व्यक्ति सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क, राजमार्ग आदि का इस्तेमाल करता है तो उसे इसका भुगतान करना होगा।' शीर्ष न्यायालय ने 29 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा, 'अगर किसी मोटर वाहन का उपयोग 'सार्वजनिक स्थान' पर नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ नहीं ले रहा है। इसलिए उस पर ऐसी अवधि के लिए मोटर वाहन कर का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।' न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत कर लगाने का प्रावधान है और यह राज्य सरकार को मोटर वाहनों पर कर लगाने का अधिकार देती है।

क्या है मामला

पीठ ने 1985 से रसद सहायता देने के व्यवसाय में लगी एक फर्म द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि फर्म को नवंबर 2020 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की एक कॉर्पोरेट इकाई, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय डिस्पैच यार्ड में लौह और इस्पात सामग्री के संचालन और भंडारण के लिए एक अनुबंध दिया गया था। पीठ ने कहा कि कंपनी ने केंद्रीय डिस्पैच यार्ड परिसर में 36 मोटर वाहन चलाए थे। कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि केंद्रीय डिस्पैच यार्ड चारदीवारी से घिरा हुआ है

पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर सीएम रेवंत रेड्डी और बीआरएस आमने-सामने, विधानसभा में हुई गरमा गरम बहस

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। मुद्दा था पिछड़ा वर्ग आरक्षण और बीआरएस की भूमिका। मुख्यमंत्री ने बीआरएस पर गंभीर आरोप लगाए कि वह पिछड़े लोगों के सशक्तिकरण के खिलाफ रही है, वहीं बीआरएस ने सरकार पर चुनौती दी कि वह पिछड़े वर्ग के लिए बिल पास कराने के लिए सच्चा संघर्ष दिखाए।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पिछड़ो लोगों के सशक्तिकरण के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछड़ा आरक्षण को लेकर बड़ा धरना हुआ, तब बीआरएस ने उसका समर्थन नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह साफ सबूत था कि बीआरएस को पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ाने में कोई ईमानदारी नहीं है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीआरएस ने राज्यपाल पर दबाव डालकर पिछड़े वर्ग के आरक्षण अध्यादेश को रोका।

पिछड़ा वर्ग के समर्थन का दावा

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह भी कहा कि जनता पहले ही बीआरएस के खिलाफ जनादेश दे चुकी है। उन्होंने दोहराया कि सरकार पिछड़ा समुदाय के अधिकारों को लेकर गंभीर है और इस बार उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेगी। रेवंत रेड्डी का कहना था कि बीआरएस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती रही है, जबकि जमीनी स्तर पर उसने पिछड़ा वर्ग को कभी वास्तविक शक्ति नहीं दी।

बीआरएस का पलटवार

मुख्यमंत्री के आरोपों पर बीआरएस नेता केटीआर ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी सचमुच पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करनी चाहिए, जब तक कि पिछड़ा बिल पास न हो जाए। केटीआर ने कहा कि यह सिर्फ बैठकों और नियुक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि असली समर्पण दिखाने का समय है। उन्होंने रेवन्त रेड्डी को याद दिलाया कि जिस तरह केसीआर दिल्ली गए थे और घोषणा की थी कि वह तेलंगाना के गठन तक वापस नहीं लौटेंगे, उसी तरह मौजूदा मुख्यमंत्री को भी दिल्ली में डटे रहना चाहिए।

अमेरिकी शुल्क से जयपुर, जोधपुर सहित पूरे राजस्थान के हस्तशिल्प निर्यातक परेशानः गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों से राज्य के हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े निर्यातक परेशान हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हस्तशिल्प के प्रमुख केंद्र जयपुर और जोधपुर इस स्थिति का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं। गहलोत ने चेतावनी दी कि निर्यात में कमी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है और इन उद्योगों में कार्यरत कारीगरों और श्रमिकों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने स्थिति को अप्रिय बताया और केंद्र से शुल्कों से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा ''केंद्र सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे तथा निर्यातकों को भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उनके साथ हर स्थिति में खड़ी है ताकि उनका मनोबल प्रभावित न हो एवं सभी की आजीविका चलती रहे।''

भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के करेगा दो बड़े पनडुब्बी सौदे

नई दिल्ली। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत के मद्देनजर भारत हिंदू महासागर में अपनी समुद्री युद्ध क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। इसी के तहत अगले साल के मध्य तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के दो बड़े पनडुब्बी सौदों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि पहली परियोजना तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद की है। इस पर बातचीत चल रही है। इनका निर्माण सरकारी कंपनी मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) और फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख नेवल ग्रुप की ओर से संयुक्त रूप से किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने करीब 36,000 करोड़ रुपये के इस सौदे को दो वर्ष पहले मंजूरी दे दी थी, लेकिन परियोजना के विभिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत में देरी हुई है। रक्षा मंत्रालय की जिस दूसरी परियोजना पर नजर है, वह लगभग 65,000 करोड़ रुपये की लागत से छह डीजल-इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बियों की खरीद है। इस खरीद को मंत्रालय ने 2021 में ही मंजूरी दी थी। सूत्रों ने बताया कि उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक दोनों सौदों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

जर्मनी कंपनी ने की साझेदारी

सूत्रों ने बताया कि अग्रणी जर्मन जहाज निर्माता कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) ने छह डीजल-इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बियों से जुड़ी परियोजना के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इसे हाल के वर्षों में सबसे बड़ी मेक इन इंडिया पहल में से एक बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सौदे के लिए लागत पर बातचीत जल्द ही शुरू होगी और अनुबंध पूरा होने की पूरी प्रक्रिया में छह से नौ महीने का समय लग सकता है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया (पी75-आई) के तहत छह स्टील्थ पनडुब्बियों का प्रस्तावित अधिग्रहण एक पूरी तरह से नया कार्यक्रम है। इसमें तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की योजना पिछले अधिग्रहण का अनुवर्ती आदेश होगी। नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) की ओर से नौसेना समूह के सहयोग से छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

नौसेना की इच्छा, जल्द हों सौदे

एक अधिकारी ने बताया कि नौसेना चाहती है कि दोनों सौदे शीघ्र ही पूरे हो जाएं, क्योंकि वह अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि डीजल इंजन कार्यक्रम के लिए लागत वार्ता प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में समय लगेगा। स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए वाणिज्यिक वार्ता लगभग पूरी हो चुकी है।

गृहमंत्री अमित शाह केवल बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं : उमर अब्दुल्ला

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सप्ताह की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में बादल फटने और रिकॉर्ड बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को यह जानकारी दी।

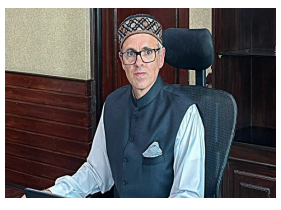

शाह का रविवार शाम दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचने और सोमवार को राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने से पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम है। अधिकारियों के मुताबिक 14 अगस्त से अब तककिश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण 130 से अधिक लोग मारे गए और 120 से अधिक घायल हो गए, जबकि 33 लापता हैं।

अब्दुल्ला ने कहा, ''केंद्रीय गृह मंत्री केवल भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने और केंद्र से हमारी आवश्यकताओं (संकट से निपटने के लिए) को देखने के लिए यहां आ रहे हैं। उनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है और वह सुरक्षा या विकास की समीक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं।''

मुख्यमंत्री ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के बाद उधमपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह राजभवन में बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे। राजमार्ग रविवार को छठे दिन भी बाधित रहा।

पंजाब में बाढ़ का कहर जारी! व्यास समेत नदियाँ उफान पर, 24 की मौत, लाखों एकड़ फसल तबाह

चड़ीगढ़। पंजाब में रविवार को बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि कई ज़िलों में लगातार बारिश हो रही है और घग्गर व व्यास नदियाँ उफान पर हैं। पंजाब में बाढ़ से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के नौ जिलों में रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के उफान के कारण 1,018 गाँव प्रभावित हुए हैं और 1.51 लाख एकड़ (61,273 हेक्टेयर) में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फसलों के नुकसान और पशुओं की मौत के कारण राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।

जिला मुख्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, फाजिल्का में 16,632 हेक्टेयर, फिरोजपुर में 10,806 हेक्टेयर, कपूरथला में 11,620 हेक्टेयर, पठानकोट में 7,000 हेक्टेयर, तरनतारन में 9,928 हेक्टेयर और होशियारपुर में 5,287 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है।

पंजाब में कपूरथला जिला प्रशासन ने सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र के लोगों से लगातार बारिश के बाद ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर रविवार को अलर्ट जारी कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कपूरथला के उपायुक्त अमित कुमार पांचाल ने बताया कि भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर 2.35 लाख क्यूसेक तक बढ़ गया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है।

मौसम विभाग ने कपूरथला जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पांचाल ने कहा कि लोगों की जान बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है इसलिए प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सेना और राज्य आपदा मोचन बल के दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचा रहे हैं।

सुल्तानपुर लोधी और भुलत्थ इलाके के गांव बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सतलुज, व्यास एवं रावी नदियां उफान पर हैं और पंजाब बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित गांव पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों के हैं।

मानव-पशु संघर्ष से निपटने में सहयोग नहीं कर रही केंद्र सरकार : विजयन

तिरूवनन्तपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए राज्य के साथ सहयोग नहीं कर रही है। विजयन ने यहां वन विभाग की एक परियोजना की शुरुआत करने के अवसर पर यह बात कही। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में जंगली जानवरों के हमलों को कम करना है।

विजयन ने कहा, '' पिछले पांच वर्षों में वन्यजीवों के हमले से हुई मौत के मामलों में 79.14 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।'' मुख्यमंत्री ने दावा किया, ''वर्ष 2023-24 में 95 प्रतिशत आवेदकों को मुआवजा दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बहुत कम राशि दी गयी। यद्यपि उन्हें राशि बढ़ाने के लिए लिखा गया है, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अनुकूल निर्णय नहीं लिया गया है।''

विजयन ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा, '' मौजूदा बजट में वन्यजीवों के हमलों से निपटने के लिए परियोजनाओं के लिए 70 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।''

विजयन ने आरोप लगाते हुए कहा, ''केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उदाहरण के लिए, हमने उनसे कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों को हिंसक जानवर घोषित करने का अनुरोध किया। लेकिन केंद्र ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।''

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का रुख यह है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत सूचीबद्ध जंगली जानवरों को, चाहे वे जंगल के भीतर हों या बाहर, वन्यजीव माना जाना चाहिए और कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता।

'दो सागर' होने के बावजूद सूखे रहे पालिका के कृत्रिम 'सागर'

डेढ़ दिनी गणपति विसर्जन पर ठेकेदार की लापरवाही, प्रशासन मौन

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। जहां दो सागर हों, वहां महासागर की उम्मीद की जाती है, लेकिन भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका में ठीक उलटा नजारा देखने को मिला। गणेश विसर्जन के लिए बनाए गए पालिका के 'कृत्रिम सागर-तालाब)' विसर्जन के दिन सूखे पड़े रहे। इस लापरवाही को लेकर अब सवाल सीधे दो 'सागर' अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल, वर्तमान में पालिका की बागडोर आयुक्त एवं प्रशासक अनमोल सागर (भा.प्र.से) के पास है, जबकि कृत्रिम सागर (तालाब) की जिम्मेदारी उपायुक्त बालकृष्ण क्षीरसागर को सौंपी गई थी। ऐसे में गणेश भक्तों के मन में सवाल उठ रहा है कि दो-दो सागर होते हुए भी सागर क्यों सूख गए?

गौरतलब है कि डेढ़ दिनी गणपति विसर्जन के लिए पालिका ने लगभग 18 लाख रुपये का ठेका निकालकर 10 कृत्रिम सागर (तालाब) तैयार करवाए थे। इनमें कुछ पक्के और कुछ बड़े-बड़े टबों के माध्यम से तालाब बनाए गए। सुशोभीकरण से लेकर सारी व्यवस्था का जिम्मा मिलिंद मुड़े नामक ठेकेदार को सौंपा गया था। लेकिन विसर्जन के दिन केवल सात तालाबों में ही विसर्जन संभव हो सका, जबकि तीन तालाब पूरी तरह फेल साबित हुए। ठेकेदार इन तालाबों में पानी की ही व्यवस्था नहीं कर पाया।

सूत्रों की मानें तो यही ठेकेदार पिछले कई वर्षों से लगातार इस काम का ठेका लेता आ रहा है। सवाल यह है कि ठेकेदार की इस लापरवाही पर प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करेगा या पूर्व की भांति आंखें मूंदकर बैठा रहेगा। खास बात यह है कि पर्यावरण विभाग से लेकर उपायुक्त और आयुक्त तक सभी अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

भिवंडी के गणेश भक्तों का कहना है कि जब पालिका ने लाखों रुपये खर्च कर कृत्रिम तालाब बनाए, तो विसर्जन के दिन तालाबों में पानी न होना गंभीर लापरवाही है। ऐसे में 'दो सागर' नामक अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ठेकेदार पर शिकंजा कसता है या मामला फिर ठंडे बस्ते में डाला जाएगा।

हालांकि इस अव्यवस्था को देखते हुए 29 अगस्त को पालिका के अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके ने विसर्जन घाटों का बंटवारा करते हुए चार मुख्य अधिकारियों को अलग अलग विसर्जन घाटों की जिम्मेदारी सौंप दी है। जिसमें नदीनाका,शेलार,चाविद्रा और पोगांव विसर्जन घाट उपायुक्त (कर) बालकृष्ण क्षीर सागर व उनके सहयोगी परवाना व जाहिरात प्रमुख स्नेहल पुण्यार्थी को सौंपी गई है। इसी तरह कामतघर, वाराला देवी और फेणेगांव विसर्जन घाटों की जवाबदेही उपायुक्त (मुख्यालय) विक्रम दराडे व आपातकालीन विभाग प्रमुख शाकीब खर्बे, नारपोली विसर्जन घाट की जिम्मेदारी प्रभारी आरोग्य अधिकारी संदीप गाडेकर व प्रभारी वाचनालय विभाग प्रमुख सुदाम जाधव भत भादवड़ विसर्जन घाट की जिम्मेदारी प्रभारी उप अभियंता पानी (पुरवठा विभाग) संदीप पटनावर व प्रभारी सहायक आयुक्त (चुनाव विभाग) नितिन पाटिल को सौंपा गया है।

भिवंडी में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ शातिर गिरफ्तार

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट-2 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक शातिर आरोपी को अवैध हथियार के साथ लेकर घूम रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत जाल बिछाकर भादौड़ से बिलाल नगर जाने वाली पाइपलाइन के पास ट्रांसफार्मर के नजदीक आरोपी को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उसके पास से देशी माऊजर पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नफीस उर्फ तोतला दिलावर खान (23 वर्ष, निवासी शांति नगर, भिवंडी) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में गु.र.नं. 900/2025 के तहत शस्त्र अधिनियम 1959 की कलम 3, 25 व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की कलम 37(1), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में पुलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव, सहायक पुलिस आयुक्त शेखर बागडे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवणे के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक मिथुन भोंडे, पो.नि. रंजीत पाटिल, स.पो.नि. सुधाकर चौधरी समेत पुलिस कर्मचारी वासरे, राणे, पाटिल, घाग, मोघेता/डोंगरे, ढांगले, खरत और कुम्भार शामिल रहे।क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी यह हथियार किस मकसद से लेकर घूम रहा था और इसके पीछे किस गैंग या नेटवर्क का हाथ है।

दबोच लिया। आरोपी के पास से एक देशी माऊजर पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस को खबर थी कि नफीस उर्फ तोतला दिलावर खान नामक युवक शांति नगर पाइपलाइन रोड इलाके में अवैध हथियार

भिवंडी का मौत का तालाब : प्रशासन की लापरवाही से गई एक और जान

भिवंडी (संवाददाता) । भिवंडी शहर में शनिवार रात एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही ने एक परिवार को तबाह कर दिया। दरगाह दिवान शाह परिसर के पुराने तालाब में 48 वर्षीय शकील अंसारी की डूबकर मौत हो गई। समरूबाग निवासी शकील किराए के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तालाब की सुरक्षा को लेकर भिवंडी महानगर पालिका वर्षों से लापरवाह बनी हुई है। दशकों पुराने इस तालाब की चारदीवारी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। आसपास की घनी बस्तियों में रोजाना सैकड़ों बच्चे खेलते हैं, वहीं बरसात के दिनों में तालाब लबालब भर जाता है। इसके बावजूद पालिका ने सुरक्षा दीवार की मरम्मत या नई दीवार बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

निवासियों का आरोप है कि यह हादसा कोई पहला नहीं है। इस तालाब ने पहले भी कई मासूम जिंदगियां निगली हैं। हर हादसे के बाद केवल कागज़ी खानापूर्ति कर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय किए जाते तो शकील अंसारी की जान बच सकती थी। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। नागरिकों ने मांग की है कि तुरंत सुरक्षा दीवार का निर्माण हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह तालाब जानलेवा खतरा बना रहेगा। यह दुखद हादसा महज़ एक मौत नहीं, बल्कि महानगर पालिका की नाकामी का सबूत है।

भिवंडी में गणेशोत्सव पर नेत्र चिकित्सा शिविर, 335 की जांच, 215 को मिले मुफ्त चश्मे

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। गणेशोत्सव अब केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाजोपयोगी कार्यों का भी माध्यम बनता जा रहा है। भिवंडी के धामणकर नाका मित्र मंडल ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी गणेशभक्तों के लिए नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मंडल के दिवंगत पदाधिकारी विजय गुज्जा की स्मृति में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ शनिवार शाम सहायक पुलिस आयुक्त सचिन सांगले के हाथों हुआ। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष संतोष शेट्टी, भैरव सेवा समिति के अनिल जैन, दिलीप पोद्दार, हसमुख पटेल और मोहन बल्लेवार भी उपस्थित रहे।

शिविर में शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक कुल 335 श्रद्धालुओं की नेत्र जांच की गई। इनमें से 215 लोगों को मुफ्त चश्मे दिए गए, जबकि 25 मरीजों में मोतियाबिंद की समस्या सामने आई। इन सभी मरीजों की शल्य चिकित्सा धामणकर नाका मित्र मंडल की ओर से निःशुल्क कराई जाएगी। सहायक पुलिस आयुक्त सचिन सांगले ने मंडल की सराहना करते हुए कहा कि गणेशोत्सव को सामाजिक उपक्रमों से जोड़ना एक प्रेरणादायी पहल है, जिसका अनुकरण अन्य मंडलों को भी करना चाहिए।

गौरतलब है कि यह लगातार पांचवां वर्ष है जब मंडल ने गणेशोत्सव के दौरान नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इस शिविर को सफल बनाने में आयोजन समिति के प्रमुख मुरारी पोद्दार, राकेश पटवारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विशेष प्रयास किए।

'एक वही (कापी), एक पेन' अभियान से सौजन्य मित्र मंडल ने रचाई नई परंपरा

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

गणेशोत्सव को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक चेतना से जोड़ने की मिसाल भिवंडी में देखने को मिली है। सौजन्य मित्र मंडल, वाणी आली ने इस बार पहली बार शहर में 'एक वही (कापी), एक पेन' की अनोखी संकल्पना साकार की है। मंडल ने गणेश भक्तों से अपील की है कि वे प्रसाद, हार-फूल लाने के बजाय शालेय उपयोगी वस्तुएं जैसे वही, पेन, पेंसिल, पट्टी, कंपास आदि गणपति बाप्पा को अर्पित करें।

इन वस्तुओं को बाद में गरीब व जरूरतमंद आश्रम शालाओं के आदिवासी विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाएगा, जिससे उनकी शैक्षणिक मदद हो सके। मंडल का मानना है कि शिक्षा ही समाज और देश के विकास की कुंजी है। इसी उद्देश्य से इस पहल को गणेशोत्सव जैसे बड़े सामाजिक पर्व से जोड़ा गया है। इस अनोखे देखावे में शैक्षणिक साहित्य का प्रयोग करके न केवल शिक्षा का महत्व बताया गया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया है।मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि इस पांच दिवसीय गणेशोत्सव के बाद भी अनंत चतुर्दशी तक यह देखावा नागरिकों के लिए खुला रहेगा। गणेश भक्त मंडल अध्यक्ष भानुदास सिंगासने, उपाध्यक्ष समीर खिसमतराव या किरण पुण्यार्थी से संपर्क कर शालेय साहित्य अर्पित कर सकते हैं।भिवंडी के नागरिकों और मान्यवरों ने भी मंडल की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गणेशोत्सव के माध्यम से समाजोपयोगी और शैक्षणिक योगदान की यह परंपरा निश्चित ही आने वाले वर्षों में प्रेरणादायी साबित होगी।

भिवंडी पालिका का भरारी पथक 'कोमा' में, आयुक्त की चुप्पी पर उठे सवाल

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।भिवंडी- निजामपुर शहर महानगर पालिका में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए गठित भरारी पथक खुद निष्क्रिय होकर 'कोमा' में चला गया है। सात सदस्यों की यह टीम कर्मचारियों की हाजिरी, ड्रेस कोड और समयपालन पर नजर रखने के बजाय पालिका कार्यालय में बैठकर सिर्फ समय गुजार रही है। नतीजा यह है कि मुख्यालय और विभागों में कर्मचारी अपनी मर्जी से देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं और नागरिकों का कामकाज ठप पड़ा रहता है।

सूत्रों के अनुसार, कई कर्मचारी ड्यूटी पर आने के बजाय निजी धंधों में लगे रहते हैं और कार्यालय में आते ही रिश्वतखोरी के जरिए मोटी कमाई कर दिन खत्म कर लेते हैं। इन पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी भरारी पथक को दी गई थी, मगर महीनों से यह टीम न रिपोर्ट बना रही है और न ही किसी कार्रवाई का अता-पता है।

सबसे गंभीर पहलू यह है कि पालिका आयुक्त अनमोल सागर (भा.प्र.से.) की चुप्पी ने भ्रष्ट कर्मचारियों का मनोबल और बढ़ा दिया है। भरारी पथक उन्हीं के आदेश पर बनाया गया था, मगर अब इसकी जवाबदेही तय करने में आयुक्त खुद पीछे हटते दिख रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि आयुक्त की उदासीनता ने भ्रष्ट कर्मचारियों को खुली छूट दे दी है। शहरवासियों का कहना है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो भिवंडी पालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार और मनमानी का अड्डा बन जाएगी। जनता की स्पष्ट मांग है कि आयुक्त तुरंत भरारी पथक को सक्रिय करें और रिश्वतखोरी व लेट-लतीफी में लिप्त कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करें। वरना यह संदेश जाएगा कि आयुक्त की चुप्पी भी भ्रष्टाचार की मौन स्वीकृति है। अब सवाल यह है कि आयुक्त अनमोल सागर जवाबदेही कब तय करेंगे – अभी, या तब जब भिवंडी की जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी ?

मालगाड़ी लॉबी भुसावल में मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत अग्रवाल द्वारा निरीक्षण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भुसावल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत अग्रवाल ने दिनांक 30 अगस्त 2025 को भुसावल स्थित मालगाड़ी लॉबी का गहन निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान आरएस वॉल डेमो की पुनरावलोकन किया गया, सीवीवीआरएस प्रणाली का विश्लेषण किया गया तथा क्रू सदस्यों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी सुझावों और फीडबैक को

जाना गया।

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, कार्यक्षमता और प्रभावी क्रू सहभागिता पर केंद्रित था। इस पहल के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को गति देना और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य था।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (प्रशासन) श्री सुनील कुमार सुमन एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

'एक का सौ' के लालच में फंस रहे है मजदूर, पुलिस प्रशासन नाकाम!?

तीन दर्जन से ज्यादा मटका अड्डे सक्रिय, विधानसभा तक गूंज चुकी है आवाज़

भिवंडी।भिवंडी में मटका जुए का कारोबार तेजी से फैल रहा है। 'एक का सौ' की लालच दिखाकर मजदूरों और गरीब तबके की दिनभर की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। हालत यह है कि शहर के अलग-अलग इलाकों में तीन दर्जन से ज्यादा अवैध अड्डे खुलेआम संचालित हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, खाड़ीपार पुल, म्हाडा कॉलोनी, कांदा-बटाटा मार्केट, तीन बत्ती परिसर, फरहान-हसीन टाकीज और पुरानी मनपा इमारत के आसपास सक्रिय चिट्ठी

राइटर्स मजदूरों को आसान पैसा कमाने का झांसा देकर कंगाल बना रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा धंधा निजामपुर पुलिस स्टेशन की सीमा में पुलिस उपायुक्त कार्यालय और सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर भी बेरोकटोक चल रहा है।

शांतिनगर, भोईवाडा, नारपोली और भिवंडी शहर पुलिस थानों के इलाकों में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी के विधायक तक विधानसभा में इस अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई का नतीजा शून्य ही रहा। फिलहाल, पुलिस उपायुक्त परिमंडल-2 के अंतर्गत आने वाले छह थाना क्षेत्रों में तीन दर्जन से अधिक मटका जुए के अड्डे सक्रिय बताए जा रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि शहर की युवा पीढ़ी और गरीब मजदूरों के भविष्य पर भी खतरे की घंटी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह अवैध धंधा पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। प्रशासन की चुप्पी और मूकदर्शक बनी पुलिस की भूमिका ने सवाल खड़े कर दिए हैं–क्या भिवंडी में मटका माफिया पुलिस से ज्यादा ताकतवर हो गया है?

मराठा आरक्षण पर गरमाई सियासत

भाजपा शरद पवार पर हमलावर, सुप्रिया सुले को आंदोलनकारियों का विरोध झेलना पड़ा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की तीखी आलोचना के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार को निशाने पर लिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि जब पवार सत्ता में थे तब उन्होंने मराठा समाज के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे पहले शनिवार को शरद पवार ने कहा था कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 52 प्रतिशत की सीमा तय की है और इसे बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है। उनके इसी बयान के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोला।

सुप्रिया सुले को प्रदर्शनकारियों का विरोध

पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले रविवार को मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे के आंदोलन स्थल पर पहुंचीं। वहां उनका सामना गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारियों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को रोका और शरद पवार के खिलाफ नारे लगाए। भाजपा के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) प्रवीण डेरेकर ने कहा कि

कई मराठा युवा शरद पवार के रुख से नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पवार लंबे समय तक राज्य और केंद्र सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन कभी मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए।

भाजपा नेताओं के तीखे सवाल

भाजपा नेता और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी पवार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'पवार चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और एक दशक तक केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन उन्होंने कभी मराठा आरक्षण के लिए पहल क्यों नहीं की? अब वे संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि जब मंडल आयोग बना या जब वे सत्ता में थे तब यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया?' पाटिल इस समय राज्य मंत्रिमंडल की उस उप-समिति के प्रमुख हैं जो मराठा समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति तथा आरक्षण की मांग से जुड़े मामलों की समीक्षा कर रही है।

शरद पवार का पक्ष

शनिवार को शरद पवार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुल आरक्षण पर 52इ की सीमा तय की है। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि तमिलनाडु में 72इ आरक्षण को अदालत ने मंजूरी दी थी। इसलिए जरूरी है कि संसद में संवैधानिक संशोधन कर इस सीमा को बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि इस विषय पर वे अन्य सांसदों से चर्चा कर रहे हैं।

क्या है मनोज जरांगे की मांग?

मनोज जरांगे मराठों के 'कुनबी' यानी कृषक जाति की पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए समुदाय को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, यह मांग अन्य पिछड़े वर्ग के संगठनों की तरफ से कड़ा विरोध झेल रही है।

मराठा आरक्षण आंदोलन में शामिल युवक की मौत, लातूर में उमड़े हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

लातूर। मराठा आरक्षण आंदोलन में हिस्सा लेने गए एक युवक की अचानक मौत से लातूर जिले में गम और गुस्से का माहौल है। रविवार को सैकड़ों लोग दिवंगत युवक विजयकुमार चंद्रकांत घोगरे को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे। उनका शव मुंबई से उनके पैतृक गांव टाकलगांव लाया जा रहा था।

आंदोलन में शामिल होने गया था मुंबई

घोगरे अपने गांव टाकलगांव से करीब 40 साथियों के साथ मुंबई गए थे। वे आज़ाद मैदान में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आंदोलन के बीच शनिवार को जब वे मुंबई के पायधोनी इलाके में घूम रहे थे, तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। साथी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।

अहमदपुर में रुका शव वाहन

जब उनका पार्थिव शरीर गांव की ओर ले जाया जा रहा था, तब अहमदपुर में बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग इकट्ठा हो गए। शव वाहन को रोककर लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां गहरा सन्नाटा और भावनात्मक माहौल देखने को मिला।

लोगों ने की सरकार से मांग

मौजूद भीड़ ने सरकार से इस मौत को गंभीरता से लेने की अपील की। लोगों ने कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि मराठा समाज की पीड़ा का प्रतीक है। भीड़ ने आरक्षण से जुड़ा मुद्दा जल्द सुलझाने की मांग की और मृतक के परिवार की मदद करने की बात उठाई।

प्रशासन ने दिया आर्थिक सहायता का आश्वासन

अहमदपुर की तहसीलदार उज्ज्वला पंगरकर मौके पर पहुंचीं और शोकसंतप्त लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की अनुशंसा भी की जाएगी।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन तेज; जरांगे बोले- मांग पूरी होने तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे

मुंबई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जहां एक तरफ मनोज जरांगे लगातार तीसरे दिन अनशन पर बैठे है। वहीं दूसरी ओर अब राज्य सरकार में भी ऊहापोह तेज हो गई है। हालांकि अभी तक फडणवीस सरकार मामले में कोई स्पष्ट और साफ हाल नहीं निकाल पाई है। इसके बाद अब जरागें ने मामले में साफ कहा है कि जब तक मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण नहीं मिलेगा, वे मुंबई नहीं छोड़ेंगे और सोमवार से वे पानी पीना भी बंद कर देंगे।

जरांगे का कहना है कि सरकार के पास खुद 58 लाख मराठाओं को कुनबी (ओबीसी में शामिल एक कृषि जाति) के रूप में दर्ज करने के दस्तावेज मौजूद हैं, इसलिए उनकी मांग संविधान के दायरे में पूरी तरह वैध है। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी में आरक्षण लेकर रहेंगे। बता दें कि मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे आंदोलन को लेकर भारी संख्या में लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पहुंचे, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्ते अपनाने की अपील की है।

मनोज जरांगे ने समर्थकों से की अपील

इसके साथ ही मनोज जरांगे ने अपील की कि प्रदर्शन में आए लोग ट्रेन से आजाद मैदान पहुंचें और वाहनों को तय पार्किंग जगहों पर रखें। उन्होंने कहा कि सरकार इस आंदोलन को

'भीड़' न समझे, ये लोग दर्द लेकर आए हैं। जरांगे ने कहा कि आंदोलनकारियों को वाशी, चेंबूर, मसीद बंदर, सिवड़ी जैसे स्थानों पर खाना पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने समर्थकों से कहा कि छाता और रेनकोट बांटने वालों को कोई पैसा न दें।

फडणवीस सरकार ने भेजा था प्रस्ताव

अनशन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को जरांगे को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की एक टीम से बातचीत कर अनशन तोड़ने का प्रस्ताव मिलने के बावजूद उन्होंने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने शनिवार को उनके प्रदर्शन की अनुमति एक दिन और बढ़ा दी है।

जरांगे ने किस वजह से की फडणवीस की आलोचना

इस दौरान मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की क्योंकि उन्होंने खुद उनके साथ बातचीत करने के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश संदीप शिंदे को भेजा था। जरांगे ने कहा कि आरक्षण देने का फैसला न्यायाधीश का काम नहीं है और उनका अनशन इसी मांग को लेकर जारी रहेगा। वहीं फडणवीस सरकार ने कहा है कि वे संवैधानिक और कानूनी ढांचे के भीतर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है।

मराठा आरक्षण पर राजनीति तेज, नितेश राणे बोले- ईडब्ल्यूएस में मिले हक; ओबीसी में शामिल करना संभव नहीं

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त गर्माहट देखने को मिल रही है। कारण है कि आज लगातार तीसरे दिन मनोज जरांग मराठा आरक्षण की मांग के लिए मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे हैं। जरांगे के इस अनशन को सैकड़ों लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, जिससे ये प्रदर्शन दिन प्रतिदिन और बड़ा होता जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज को ओबीसी में नहीं, बल्कि पहले से मौजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत आरक्षण मिलना चाहिए।

मराठा आरक्षण पर राणे का स्पष्ट रुख

मराठा आरक्षण को लेकर बढ़ते आवाज के बीच नितेश राणे ने कहा कि मराठाओं को कुनबी कहकर ओबीसी में शामिल करना पूरे महाराष्ट्र में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरांगे अगर अपनी मांग केवल मराठवाड़ा तक सीमित रखें, तो सरकार विचार कर सकती है। लेकिन

कोंकण और कई अन्य क्षेत्रों में मराठा और कुनबी दो अलग पहचान हैं और वहां के लोग यह बदलाव नहीं मानेंगे।

माराठाओं को ओबीसी आरक्षण देना संभव नहीं- राणे

मामले में राणे ने साफ कहा कि मराठाओं को ओबीसी आरक्षण देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही उनके लिए ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। यदि इसे बढ़ाने की मांग है, तो सरकार के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही राणे ने आरोप लगाया कि एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार, जरांगे के आंदोलन को वित्तीय मदद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर रोहित पवार इनकार करते हैं तो मैं सबूत दूंगा।

चंद्रकांत पाटिल बोले - जाति से नहीं, आर्थिक हालात से पिछड़े हैं मराठा

वहीं इस मामले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मराठा समाज ने कभी छुआछूत या सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं किया, लेकिन कृषि से आय घटने और शिक्षा महंगी होने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ईडब्यूएस के तहत 10% आरक्षण पहले ही दिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी है। मराठा समाज को इसी रास्ते से मदद मिल सकती है।

क्या चाहते हैं जरांगे?

अब बात अगर जरांगे की मांग की करें तो अनशन पर बैठे जरांगे चाहते हैं कि मराठाओं को कुंभी जाति के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि कुंभी ओबीसी श्रेणी में आते हैं, जिससे मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठाओं को कुंभी घोषित कर आरक्षण देना चाहिए और हैदराबाद और सातारा के गजट नोटिफिकेशन को कानून बनाया जाए। हालांकि ओबीसी नेता इस मांग का विरोध कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में गरमाया आरक्षण का मुद्दा, चंद्रकांत पाटिल बोले- जरूरत पड़ी तो जरांगे से मिलेंगे सीएम

मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर राज्यभर में जारी सियासी गर्माहट के बीच मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। इसी बीच मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। पाटिल ने जरांगे द्वारा सीएम फडणवीस की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कभी अड़ियल नहीं रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो सीधे तौर पर भी मामले में हस्तक्षेप करेंगे। बता दें कि पाटिल यहां इस बात का जवाब दे रहे थे जब जरांगे ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे को बातचीत के लिए भेजे जाने की बात को लेकर सीएम फडणवीस की आलोचना की थी।

क्या बोले च्रंदकांत पाटिल?

जरांगे की आलोचना का जवाब देते हुए रविवार को मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री खुद भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कभी अड़ियल नहीं रहे हैं। आमतौर पर लोग सीएम से मिलने जाते हैं, लेकिन अगर इस मामले में बात और आगे बढ़ी साथ ही इसका समाधान निकलने की संभावना बना तो सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद भी जरांगे से

मिलने जा सकते हैं। इसके साथ ही पाटिल ने ये भी कहा कि सीएम फडणवीस सच को भी कड़वे शब्दों में नहीं कहते, जबकि अजीत पवार स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं।

समझिए क्या है जरांगे की मांग?

अब बात अगर जरांगे की मांग की करें तो अनशन पर बैठे जरांगे वे 10इ आरक्षण की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि मराठाओं को कुंभी जाति के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि कुंभी ओबीसी श्रेणी में आते हैं, जिससे मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठाओं को कुंभी घोषित कर आरक्षण देना चाहिए और हैदराबाद और सातारा के गजट नोटिफिकेशन को कानून बनाया जाए। हालांकि ओबीसी नेता इस मांग का विरोध कर रहे हैं।

अजित और शरद पवार के बीच बयानबाजी

मामले में एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 52इ तय की है, लेकिन तमिलनाडु में 72इ आरक्षण को मंजूरी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। दूसरी ओर शरद पवार के इस टिप्पणी पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जो यह बातें बता रहे हैं, वो खुद कई वर्षों तक सत्ता में थे। वे आदरणीय हैं, लेकिन मुझे और कुछ न बोलवाएं।

मराठा समुदाय के सपनों को पंख देने वाला संगठन - सारथी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास हेतु सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण और शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अर्थात् मराठा, कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा, के समग्र विकास के लिए 2019 से 'सारथी' नामक संगठन की शुरुआत की है। मराठा समुदाय के सपनों को पंख देने वाले एक संगठन के रूप में, 'आओ शाहू विचारों को गति दें, सर्वांगीण प्रगति करें' के आदर्श वाक्य के तहत, छत्रपति शाहू महाराज शोध, प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्थान (सारथी), पुणे शिक्षा, मार्गदर्शन, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के सभी क्षेत्रों में 63 विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहा है।

2021-22 से 2024-25 तक के चार वर्षों में, 8 लाख 38 हज़ार 477 लाभार्थी सारथी संस्थान में शामिल हो चुके हैं और कई छात्र इस संस्थान से मार्गदर्शन प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब तक इस संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन पर 647 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सारथी संस्थान के छात्र हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।

शैक्षणिक अवसर और छात्रवृत्ति योजनाएँ

सारथी के माध्यम से, छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए पूर्व-प्रशिक्षण, साक्षात्कार की तैयारी और मार्गदर्शन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सारथी की स्थापना के बाद से, 2020 से 2024 तक 112 छात्र विभिन्न संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में चयनित होकर सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग में 2020 से 2023 तक 1048 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जिनमें से 229 छात्र कक्षा एक में और 819 छात्र कक्षा दो में चयनित हुए हैं।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सारथी के माध्यम से संचालित छत्रपति संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तित्व विकास एवं कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य के सभी तालुका स्तरों पर संचालित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। 2022 से 2025 तक एक लाख 20 हज़ार लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना था, जिनमें से 97 हज़ार 286 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 34 हज़ार 304 लाभार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इनमें से 7365 लाभार्थियों को नौकरी मिल चुकी है और 9418 लाभार्थियों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में, 17 हज़ार 251 लाभार्थी महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो-जर्मन टूल रूम कौशल प्रशिक्षण पहल

इस पहल के अंतर्गत, छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, पुणे और कोल्हापुर में आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्रीधारी 1012 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इनमें से 657 छात्रों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 314 छात्रों को नौकरी मिल गई है।

विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

विदेश में शिक्षा के लिए मेधावी छात्र-छात्राओं हेतु महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सारथी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कुल 50 छात्रों का चयन किया गया। इन छात्रों को आज अंततः कुल छह करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि का लाभ दिया गया। वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत कुल 75 छात्रों का चयन किया गया है। वर्ष 2025 के लिए 75 सीटों के लिए 16 जून, 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे और चयन प्रक्रिया जारी है।

डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षा घरेलू छात्रवृत्ति

देश के 200 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 300 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क और भोजन शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत 441 छात्रों का चयन किया गया है और उन्हें 5 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 270 छात्रों का चयन किया गया है। मार्च 2025 के अंत तक इस योजना के लिए 6 करोड़ रुपये का लाभ दिया जाएगा।

उभरते कृषि-औद्योगिक क्षेत्र में शैक्षिक अवसरः शैक्षिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पुणे में औद्योगिक किण्वन एवं अल्कोहल प्रौद्योगिकी (आईएफएटी) और वाइन ब्रूइंग एवं अल्कोहल प्रौद्योगिकी (डब्ल्यूबीएटी) के छात्रों के लिए एक शैक्षिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है और इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी पात्र छात्रों को 100 प्रतिशत शैक्षिक शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है।

चेन स्नेचिंग की जांच में गई पुलिस टीम पर हमला, एक आरोपी का एनकाउंटर, दूसरा घायल

सतारा। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें लोकल क्राइम ब्रांच (थ्ँ) के पुलिसकर्मी चेन स्नेचिंग के मामले की जांच करते हुए हमले का शिकार हो गए. आरोप है कि अपराधियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. इस कार्रवाई में दो आरोपी घायल हो गए, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई.

महिलाओं से मंगलसूत्र लूट की घटना से दहशत

घटना की शुरुआत 28 अगस्त की सुबह हुई, जब सतारा शहर के एक पॉश इलाके में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिलाओं को बदमाशों ने चाकू की नोंक पर डरा-धमकाकर उनके गले से मंगलसूत्र छीन लिए. इस वारदात से पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया और स्थानीय समाज में भारी आक्रोश फैल गया. नागरिकों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए और मामले की त्वरित जांच की मांग की.

अपराधियों की तलाश में पुणे पहुंचे पुलिसकर्मी

इस घटना के बाद सतारा लोकल क्राइम ब्रांच की एक टीम जांच में जुट गई. जांच के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी पुणे जिले के शिरूर तालुका स्थित शिक्रापुर के इलाके में छिपे हुए हैं. पुलिस टीम ने तुरंत वहां दबिश दी.

दबिश के दौरान पुलिस पर हमला

जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची, तो एकाएक दोनों आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में क्राइम ब्रांच के दो सिपाही घायल हो गए. आरोपियों ने मौके से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया.

एनकाउंटर में एक घायल, एक की मौत

आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक आरोपी लखन भोसले को पीठ में गोली लगी. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. दूसरा आरोपी भी पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तत्काल पुणे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने की पुष्टि

सतारा के पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमारे दो जवान इस हमले में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सम्पादकीय

आम जीवन सरल बनाने में मदद कीजिए

सरकारों का काम आदमी के जीवन को सरल बनाना है।तकनीक के माध्यम से उसे ऐसी सुविधांए देना है कि वह परेशान न हो, किंतु भारत में हो इसके विपरीत रहा है। उन्हें अलग -अलग काम के लिए थोड़ी- थोड़ी बात के लिए परेशान किया जा रहा है। उनके जीवन को दुरूह किया जा रहा है।

आज सबसे बड़ी परेशानी हैं बैंको में जाकर खाते की केवाईसी कराने की।बैंकों की केवाईसी के नाम पर बैंक खाताधारक को परेशान किया जा रहा है।हालत यह है कि केवाईसी करानी है, इसकी उसे सूचना भी नही मिलती। उसे उसके लिए बैंक की ओर से मैसेज भी नही आता।

मेल आनी चाहिए। किंतु ऐसा हो नही रहा। वैसे प्रत्येक ट्रांजेक्शन के मैसेज आते रहते हैं। केबाईसी कराना है, इसका पता तब चलता है जब खातेधारक के चैक का भुगतान रोक दिया जाता है। वह पेमेंट नही कर पाता ।भुगतान रोकने के कारण चैक जारी करने वाले पर संबधित बैंक या सस्थाएं चार सौ से आठ सौ रूपये तक का जुर्माना लगा देती है।मैंने पिछले साल ओरियंटल इंशोरेंस कंपनी को अपनी मेडिक्लेम पोलिसी के लिए चैक दिया। चैक बैंक गया तो भुगतान रूक गया। मैं बैंक गया। बैंक प्रबंधक ने खाता देखकर कहा कि खाता आपका जारी है। चैक का भुगतान कैसे रूका पता नहीं। उनके एक स्टाफ ने देखकर बताया कि खाता बंद किया हुआ है। बैंक प्रबंधक ने कहा कि अब सब कंप्यूटराइज है। हमें पता नही चलता और खुद जाता है। बैंक स्टाफ के पता है या नही । इससे खाताधारक को क्या लेना। मेरे से तो इंशोरेंस कंपनी ने चैक डिस ओनर होने के छह सौ रूपये अतिरिक्त वसूल लिए।मुझे तो फालतू का छह सौ रूपये का दंड़ पड़ गया।

अभी लाकर आपरेट करने बैंक जाना पड़ा तो बैंक स्टाफ ने कहा कि इसकी केवाईसी कराईये। हमने कहा कि अभी खाते की तो कराई है।उनका कहना था कि बैंक लॉकर की भी करानी है। लॉंकर बैंक के खाते से जुड़ा है, यह बताने पर भी बैंक कर्मी नही माने।यदि आपके पास चार- पांच बैंक खाते हैं तो प्रत्येक दो साल से केवाईसी कराने जरूर जाना होगा।

अभी तक बैंक खाते चालू रखने के लिए केवाईसी करानी थी।अब बिजली विभाग के मैसेज आ रहे हैं, कि अपने कनेक्शन की ईकेवाईसी कराईए।आज जहां चारों ओर धोखे का जाल फैला है। ठग आपको फंसाने में लगे हैं, ऐसे में किस मैसेज को सही माना जाए, किसे गलत यह कैसे पता चले। अभी परिवहन विभाग का मैसेज आया है कि आधार आथोराइजेशन माध्यम से अपने ड्राइविंग लाइसैंस पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। समझ नही आ रहा कि क्या- क्या कराएं। हम पर ये सब करना नही आता।इसका मतलब ये की रोज जनसेवा केंद्र पर जाइये। लाइन में लगिए और पैसा भी दीजिए। लगता है कि कहीं ये जनसेवा केंद्र की आय बढ़ाने के लिए तो नही किया जा रहा।

अभी पिछले दिनों आदेश आया कि अपना आधार कार्ड प्रत्येक दस साल में अपडेट कराना है।मैं छोटे शहर में रहता हूं। यहां कि आबादी दो लाख के करीब है। पूरे शहर में आधार कार्ड अपडेट कराने का एक ही सैंटर है। मुख्य डाकघर। उसमें आधार कार्ड बनवाने वालों की सवेरे आठ बजे से लाइन लग जाती है।हम 75 साल से ऊपर के पति -पत्नी कैसे उस लाइन में लगें , ये कोई सोचने और बताने वाला नही है। दूसरे केंद्र का दरवाजा खुलने पर इस तरह धक्का-मुक्की होती है कि हम लाइन में लगे तो हाथ - पांव तुड़ाकर जरूर अस्पताल जांएगे।

केद्र सरकार / रिजर्व बैंक को आदेश करना चाहिए कि बैंक अपने यहां अतिरिक्त स्टाफ रखे। उसक कार्य सिर्फ खातेधारकों से समय लेकर उनके खातों की केवाईसे कराना हो।सरकार जिस तरह वोट बनवाती है। वोटर का वेरिफिकेशन कराती है। उसी तह से केवाईसी कराई जाए।इसके बैंक खाता धारकों को सुविधा होगी।केवाईसी कराने के लिए रखे जाने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा।यही काम राज्य की बिजली कंपनी कर सकती हैं। विभागीय मीटर रीडर माह में एक बार रीडिंग लेने उपभोक्ता के घर जाते हैं। वे ही उपभोक्ता से केवाईसी के पेपर लेले।मीटर रीडर को उपभोक्ता जानते हैं उन्हें पेपर देते किसी उपभोक्ता को परेशानी भी नही होगी।मीटर रीडर आफिस आकर इस कार्य में लगे स्टाफ को पेपर देकर केवाईसी कराए।हो यह रहा है कि संबधित विभाग बैंक/ बिजली अपना कार्य उपभोक्ता पर डाल उसके जीवन को कठिन बना रहे हैं, जबकि उन्हे अपने ग्राहकों को सुविधांए देनी चाहिए थीं। ऐसा ही आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। हां इसके लिए उपभोक्ता से थोड़ा बहुत चार्ज लिया जा सकता है।अभी एक मैसेज आया कि आपका इन्कमटैक्स का रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है। मैंने अभी रिटर्न भरा नही, सो ये मैसेज बेटे को भेज दिया कि शायद उसने रिटर्न भरा हो । उसका जबाब आया कि पापा इस मैसेज के लिंक पर क्लिक मत करना । ये गलत लगता है।

आज सबसे बड़ी समस्या है कि सही और गलत का कैसे तै हो।किसी न किसी तरह धोखे में लेकर रोज हजारों व्यक्ति रोज ठगे जा रहे हैं।इससे कैसे बचा जाए?ऐसे हालात में जीवन दुरूह होता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को आम आदमी का जीवन को सरल बनाने के लिए काम करना चाहिए।

मोदी के चीन जाने से पहले ही ट्रंप ने ले लिया एक और बड़ा फैसला, निकाले जाएंगे लाखों भारतीय?

भारत पर टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं, जिससे लाखों भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लौटना पड़ सकता है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को डबल झटका लगने वाला है। दरअसल, अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं। वो पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। खासकर अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने वाले भारत के खिलाफ ट्रंप जो अपना नफरती एजेंडा चला रहे हैं। उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। या तो उन्हें भारत की तरक्की पसंद नहीं आ रही है, या फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। टैरिफ के बाद अब ट्रंप की नजर अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों पर है। यानी की अब भारतीयों की नौकरी पर भी खतरे की घंटी बजने लगी है। इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिकी वीज़ा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन का संकेत दिया है, जिसमें लॉटरी-आधारित आवंटन शामिल है। आव्रजन, अमेरिका में सबसे अधिक ध्रुवीकरण करने वाले विषयों में से एक रहा है, जहाँ ट्रंप सरकार विदेशियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस तरह की जाँच देश में एच-1बी वीज़ा धारकों की स्थिति पर भी लागू हो रही है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में जन्मे लोग एच-1बी कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से हर साल स्वीकृत होने वाले सभी एच-1बी आवेदनों में से 70 प्रतिशत से अधिक भारतीयों के हैं। चीन में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं, जो 2018 से 12-13 प्रतिशत के आसपास मँडरा रहे हैं।

अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने एच1बी वीजा पर रोक लगाने की संभावना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल के जवाब में सवाल उठाया है कि क्या अब एच1बी वीजा पर रोक लगाने का समय आ गया है। यानी की उन्होंने एच1बी वीजा को रोकने की मांग कर डाली है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि बड़ी टेक कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर एच1बी वीजा कर्मचारियों को भर्ती करती हैं। जो अमेरिकी पेशेवरों के साथ अन्यायपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि कंपनियां हजारों कर्मचारियों को निकालने के बाद भी विदेश वर्क वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके पहले रिपब्लिकन कांग्रेसी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भारतीयों को एच1बी वीजा जारी करना बंद करने का सुझाव दिया था। ग्रीन ने आरोप लगाया था कि भारतीय प्रोफेशनल अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं।

एच-1बी नॉन-इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष व्यवसायों में अस्थायी रूप से विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ऐसे व्यवसायों को कानून इस रूप में परिभाषित करता है कि उनके लिए अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट विशेषता में स्नातक (बैचलर) या उच्च डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता की आवश्यकता होती है। ये वीजा तीन साल के लिए जारी होता है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर साल अमेरिकी सरकार 65000एच1बी वीजा जारी करती है। जबकि 20 हजार अतिरिक्त वीजा अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर या पीएचडी करने वालों के लिए जारी किए जाते हैं।

भारत लंबे समय से एच1बी वीजा का लाभ लेने वाला देश रहा है, विशेषरूप से आईटी और टेक्नोलॉजी पेशेवरों के लिए। हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर और शोधकर्ता एच1बी वीजा से अमेरिका जाते हैं। अगर नियम सख्त किए गए या रोक लगाई गई तो इसका सीधा असर भारत के आईटी सेक्टर या भारतीय टैलेंट पर पड़ेगा।

गौरतलब है कि भारत में जन्मे लोग एच-1बी कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से हर साल स्वीकृत होने वाले सभी एच-1बी आवेदनों में से 70 प्रतिशत से ज़्यादा भारतीय हैं। चीन में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं, जो 2018 से 12-13 प्रतिशत के आसपास मँडरा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच, एच-1बी कार्यक्रम के तहत जारी किए गए लगभग 4 लाख वीज़ा में से 72 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को मिले। इसी अवधि के दौरान, अमेरिका में मौजूद शीर्ष चार भारतीय आईटी कंपनियों - इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विप्रो - को लगभग 20, 000 कर्मचारियों को ๒-1 वीज़ा पर काम करने की मंज़ूरी मिली, जैसा कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के आंकड़ों से पता चलता है।

अमेरिका में एच-1बी वीज़ा की बढ़ती आलोचनाओं के बीच, भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि इन वीज़ा का फ़ायदा अंततः अमेरिकी टेक कंपनियों को ही मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अधिकारियों ने स्वीकार किया कि एच-1बी वीज़ा, जिसके प्रमुख लाभार्थी भारतीय हैं, पर प्रतिबंध भारत के आईटी क्षेत्र और उसके कर्मचारियों पर असर डाल सकते हैं। यह निश्चित रूप से अमेरिका में भारतीय कामगारों की पहुँच को सीमित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ की आईटी कंपनियों को अमेरिका-आधारित अनुबंध मिलेंगे, जिससे उनके राजस्व में कमी आ सकती है। लेकिन वीज़ा ने अमेरिकी कंपनियों को दुनिया भर में सही कर्मचारी ढूँढ़ने में काफ़ी मदद की है, और क्या वे इसकी जगह अमेरिकी लोगों को ला पाएँगी, यह स्पष्ट नहीं है। निश्चित रूप से यह कोई आसान बदलाव नहीं है।

इन्फ्लूएंसरों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग आखिर कब तक

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की भी मजाक उड़ाना या उपहास का पात्र बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले कुछ सालों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग आम होता जा रहा है। यहां तक कि स्वतंत्रता के नाम पर समाज में वैमनस्य बढ़ाना, वर्ग विशेष के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना इन उपहास कर्ताओं के लिए तो सामान्य होता जा रहा है तो राजनीतिक व सोशल एक्टिविस्ट भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की सरकार को गाइड लाईन जारी कर सीमाओं में बांधने और इस तरह के इन्फ्लूएंसरों के खिलाफ सख्त टिप्पणी व उसी स्तर की सार्वजनिक माफी मांगने के निर्देश आवश्यक हो गए थे। हालांकि यह आदेश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी एसएमए से पीड़ित व्यक्तियों का समय रैना व अन्य द्वारा उपहास उड़ाने से संबंधित प्रकरण में दिए गए हैं। आदेश में दिव्यांगों का उपहास करने को गंभीरता से लिया गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिस स्तर पर उपहास उड़ाया गया ठीक उसी स्तर पर माफी भी मांगी जाए। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि माफी की औपचारिकता से काम नहीं चलने वाला है।

व्यूअरशिप, फोलोवर्स या व्यूज बढ़ाने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया या यों कहे कि इंटरनेटी संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी को भी उपहास का पात्र बनाना आम होता जा रहा है, उस पर लगाम की आवश्यकता लंबे समय से चली आ रही थी और ऐसे में देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची द्वारा की गई टिप्पणी ऐसे तत्वों और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल फूहड हास्य कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रस्तुत सामग्री में मीडिया इन्फ्लूएंसरों द्वारा लोगों का बैखोफ उपहास उड़ाया जाना आम होता जा रहा है। ऐसे लोग अपने आपको समाज के विशिष्ट व्यक्ति बनने और दिखाने का प्रयास करते हैं। दावा करते है कि उनके इतने फोलोवर्स है या इतने व्यूअर्स है। पर सवाल यह उठता है कि किसी की मजाक उडाने या उपहास करने का अधिकारी आपको कौन देता है। हेट स्पीच और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के दुष्परिणाम सामने हैं। छोटी सी टिप्पणी कभी कभी तो असामाजिक तत्वों के लिए अच्छा अवसर बन जाती है और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने तक की सीमा तक पहुंच जाती है। मजे की बात यह है कि हेट स्पीच या ऐसी टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई होते ही तथाकथित वुद्धिजीवियों की टीम सक्रिय हो जाती है। यह तथाकथित कोमेडियन और सोशल इन्फ्लूएंसर अपनी टिप्पणियों की बदौलत व्यूअरशिप बढ़ाते हैं और अनाप शनाप पैसा कमाते हैं, अपनी जेब भरते है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत टिप्पणी नहीं मानते हुए व्यावसायिक गतिविधि करार दिया है। वैसे भी सामान्य नैतिकता का सवाल भी यह उठता है कि आपकों किसी अन्य की विकलांगता या अन्य टिप्पणी को अधिकार कैसे मिल सकता है। कैसे आप किसी को उपहास का पात्र बना सकते हैं तो कैसे आप अनर्गल टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि आजकल हेट स्पीच को लेकर तो न्यायालयों में जाने का चलन बढ़ा है और यह जरुरी भी हो जाता है। सोशल मीडिया के नाम पर आप किसी की निजता पर कीचड़ नहीं उछाल सकते हैं।

यह निर्णय इस मायने में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कामेडियन्स या इन्फ्लूएंसर्स द्वारा जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां आम होती जा रही है उस पर सख्त लगाम कसना जरुरी हो जाता है। यदि इसी मामलें को देखा जाए तो एक तो ऐसे व्यक्तियों के साथ वैसे ही अन्याय हुआ है और फिर उस शारीरिक विकलांगता का मजाक उड़ाना या निशाना बनाना कहां की नेतिकता हो सकती है। इसके अलावा इंस्ट्राग्राम, वाट्सएप इसी तरह के सोशल मीडिया साइट पर अनर्गल टिप्पणियां या किसी घटना विशेष पर इस तरह की प्रतिक्रिया देकर तनाव के हालात पैदा कर देना या इसी तरह के हालात पैदा करने से आपका शौक तो पूरा हो जाता है पर उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म को सीमाओं में बांधना जरुरी हो जाता है। शहरों में आए दिन दंगे तनाव के हालात बनना आम होता जा रहा है। न्यायालय की टिप्पणी के मध्येनजर सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालकों को भी इस तरह की टिप्पणियों या सामग्री को फिल्टर करने आगे आना चाहिए। अभी तो होता यह है कि चाहे किसी भी तरह की रील हो यदि उसकी व्यूअरशिप ठीक आ जाती है तो कमाई का माध्यम बन जाती है जबकि होना यह चाहिए कि ऐसे इन्फ्लूएंसरों पर सख्ती होने के साथ ही साथ इस तरह की टिप्पणी या रील उसी व्यक्ति द्वारा करने पर ऐसे अकांउट को ब्लेक लिस्ट करते हुए ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कर दिया है। देर सबेर सरकार भी गाइडलाइन जारी कर देगी। हो सकता है सख्त प्रावधान भी कर दे पर समस्या का समाधान आसानी से होता लगता नहीं हैं। ऐसे में आम आदमी को भी आगे आना होगा तो गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनओं और खासतौर से तथाकथित वुद्धिजीवियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे आना होगा तभी कामेडियनों और सोशल इन्फ्लूएंसरों पर प्रभावी रोक संभव हो सकेगी।

सदन की गरिमा या जनता के अधिकार - गरिमा की रक्षा या जनता से दूरी?

यदि विधानसभा की कार्यवाही का सोशल मीडिया पर प्रसारण प्रतिबंधित है, तो नेताओं और दलों को भी चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज वोट मांगने के लिए रैलियों और टीवी के साथ-साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। ऐसे में सिर्फ़ सदन की कार्यवाही रोकना अनुचित लगता है। लोकतंत्र में नियम सबके लिए समान होने चाहिए, तभी व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रह सकता है। भारत में 82 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 45 करोड़ से ज़्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। टीवी दर्शकों की संख्या घट रही है और लोग सीधे मोबाइल पर ही समाचार देखना पसंद करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही को सिर्फ़ टीवी चैनलों तक सीमित रखने का फ़ैसला लोकतांत्रिक पारदर्शिता को सीमित कर सकता है। बेहतर समाधान यह होगा कि विधानसभाएँ अपने आधिकारिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, जहाँ कार्यवाही का पूरा और सच्चाई से प्रसारण हो। इस तरह सदन की गरिमा बनी रहेगी। बनाए रखा जाएगा और जनता को सूचना तक पहुँच का अधिकार भी मिलेगा।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी पारदर्शिता और जनभागीदारी है। संसद और विधानसभाएँ जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं और यही वे स्थान हैं जहाँ नीतियाँ, कानून और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे तय होते हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही तक जनता की पहुँच किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी ज़रूरत कही जा सकती है। हरियाणा राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हाल ही में लिया गया यह निर्णय कि विधानसभा की कार्यवाही अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और वेब चैनलों पर प्रसारित नहीं की जाएगी, कई अहम सवाल खड़े करता है। क्या यह निर्णय पारदर्शिता को सीमित करेगा या सदन की गरिमा को बचाएगा - यही इस संपादकीय का मूल प्रश्न है।

पिछले एक दशक में सोशल मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र में एक नई क्रांति ला दी है। पहले जहाँ लोग टीवी समाचार चैनलों या अखबारों पर निर्भर रहते थे, अब उन्हें फेसबुक लाइव, यूट्यूब स्ट्रीमिंग और ट्विटर अपडेट से तुरंत जानकारी मिल जाती है। विधानसभा या संसद जैसी संस्थाओं की कार्यवाही अब दीवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे जनता के मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचने लगी है।

यह बदलाव भी सकारात्मक रहा। आम नागरिकों, खासकर युवाओं ने, लोकतांत्रिक विमर्श में शामिल होने से उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में अपने मुद्दों पर किस प्रकार बहस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही, इसके नकारात्मक पहलू भी सामने आए। कई बार सदन में हुई गंभीर बहसों के छोटे-छोटे अंश निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए, जिनका इस्तेमाल राजनीतिक दुष्प्रचार, व्यंग्य या भ्रांतियाँ फैलाने के लिए किया गया। परिणामस्वरूप, कार्यवाही का वास्तविक उद्देश्य पीछे छूट गया और विवादों ने ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरीं।

हरियाणा राज्य विधानसभा अध्यक्ष हरिविंद्र कल्याण का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो-संदेशों से सदन की गरिमा को ठेस पहुँची है। कई बार असंसदीय शब्दों, हंगामे और व्यंग्य के छोटे-छोटे अंश बार-बार प्रसारित किए जाते हैं, जिससे जनता में नकारात्मक छवि ही बनती है। उन्होंने एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अब से केवल मान्यता प्राप्त टीवी चैनल ही कार्यवाही का सीधा प्रसारण कर पाएँगे, जबकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव या रिकॉर्डिंग डालने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। उनका यह भी तर्क है कि सदन की कार्यवाही से हटाए गए शब्दों और अंशों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करना नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसलिए, इस पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।

यद्यपि यह तर्क सतही तौर पर सही लगता है, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से यह कई सवाल भी खड़े करता है। विधानसभा जनता के करों से चलती है और वहाँ की हर गतिविधि सीधे नागरिकों से जुड़ी होती है। ऐसे में सूचना तक पहुँच को सीमित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत माना जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी टीवी नहीं देखती। वे यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहते हैं। अगर कार्यवाही सिर्फ़ टीवी चैनलों तक सीमित रहेगी, तो एक बड़ी आबादी लोकतांत्रिक बहस से वंचित रह जाएगी। जब सिर्फ़ चुनिंदा माध्यमों को ही अनुमति दी जाएगी, तो यह संदेश जाएगा कि सूचनाओं पर नियंत्रण किया जा रहा है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही कमज़ोर होगी।

भारत में 82 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 45 करोड़ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि) पर सक्रिय हैं। टीवी देखने वालों की संख्या घट रही है, जबकि मोबाइल पर समाचार देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संसद टीवी और राज्य विधानसभा चैनल बहुत कम दर्शकों तक पहुँचते हैं, जबकि यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम से लाखों दर्शक जुट सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल पारदर्शिता लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है।

बिना किसी पैरवी, घूस और भेदभाव के प्रदेश में हुआ 19, 424 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन

गरीब और ग्रामीण समाज की रीढ़ बन चुके हैं आंगनवाड़ी केंद्र : नन्दी

452 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मंत्री नन्दी ने वितरित किया नियुक्ति पत्र

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने रविवार को विकास भवन सभागार में आयोजित समारोह में सम्मिलित होकर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत प्रयागराज में नवनियुक्त 452 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उज्जवल भविष्य एवं सफल कार्यकाल की कामना की। कहा कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगीं।

मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य, संतुलित आहार और समुचित पोषण मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। स्वस्थ व्यक्ति मिलकर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस दिशा में आंगनबाड़ी केन्द्रों की भूमिका बेहद उल्लेखनीय है। किसी भी परिवार अथवा अभिभावक की आर्थिक परिस्थिति बच्चों के समग्र विकास में बाधा न बने हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है।

प्ले स्कूल में जिन सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी-भरकम फीस भरनी पड़ती है, वह आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के आधुनिकीकरण के साथ ही संसाधन युक्त बनाने के अभियान को विशेष प्राथमिकता

दी है।

इसी अभियान के अंतर्गत पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से हुई चयन प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में 19 हजार 424 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन किया गया है। जनपद प्रयागराज में 452 योग्य अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बिना किसी पैरवी के, बिना किसी घूस के, बिना किसी भेदभाव के यह चयन प्रक्रिया सम्पन्न हुई है।

आँगनबाड़ी केन्द्रों को आधुनिक बनाने की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्मार्ट टीवी, बॉटर आरओ, पोषण वाटिका की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

केन्द्रों को डिजिटल बनाने एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु स्मार्ट फोन के क्रय की कार्यवाही जारी है। प्रयागराज में 4 हजार 499 स्मार्ट फोन के क्रय की कार्यवाही प्रचलित है!

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अन्तर्गत 27 हजार 20 लाभार्थियों को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा आवेदन कराते हुए 7.20 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर करायी गयी।

आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखते हैं। यह न केवल बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि महिलाओं को भी सशक्त बनाते हैं। आज आंगनवाड़ी केंद्र गरीब और ग्रामीण समाज की रीढ़ बन चुके हैं।

इस अवसर पर जीपी कुशवाहा जिला विकास अधिकारी प्रयागराज, इंद्रबली जिला सूचना अधिकारी, टीपी सिंह एसडीएम न्यायिक, अर्थ एवं संख्या अधिकारी संतोष कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती संजीता सिंह, योगेंद्र दुबे, पुष्पा मिश्रा, इंद्रावती मौर्य, सुभाष बाजपेयी. पप्पू निमोथरिया, श्रीमती संजीता सीडीपीओ नगर प्रथम, श्रीमती अनुरागिनी सिंह, मुट्ठीगंज मंडल अध्यक्ष परमानन्द वर्मा, सुमित बागी, सोनू सिंह, सुदेश पाण्डेय एवं अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे।

वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट द्वारा इस मानसून सत्र का नौवां एवं दसवां वृक्षारोपण अभियान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बड़ोवाला तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, झिवारेडी में सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के 70 से अधिक वृक्ष रोपित किए गए। रोपित किए गए वृक्षों में गुलमोहर, कनेर, चंपा, बॉटल ब्रश, केसिया सामिया, बेलपत्र, पिलखन इत्यादि के वृक्ष शामिल किए गए।

आज का वृक्षारोपण अभियान हमारी समिति के सदस्य श्री अनुराग शर्मा जी की पूजनीय माता जी को श्रद्धांजलि दिए जाने हेतु था जिनका पिछले सप्ताह स्वर्गवास हो गया था। आज लगाए गए सभी वृक्ष पूजनीय माता जी की याद में सभी सदस्यों ने मिलकर लगाए और 2 मिनट का सबने मौन रखा। समिति द्वारा आने वाले सितम्बर महीने में देहरादून कारागार तथा केंद्रीय विद्यालय, भारतीय सैन्य एकेडमी में किए जाएंगे। उसके अलावा नदी के तट पर बांस के 100 वृक्ष भी लगाए जाएंगे।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष राम कपूर, उपाध्यक्ष रणदीप अहलूवालिया, सचिव जे पी किमोठी, कोषाध्यक्ष शंभू शुक्ला, गगन चावला, हर्षवर्धन जमलोकी, मंजुला रावत, नितिन कुमार, अमरनाथ कुमार, दिवाकर नैथानी, मनोज श्रीवास्तव, टीका थापा, सुंदर शुक्ला, शामिल रहे।

इलाज के दौरान बच्चे की मौत, डॉक्टर पर मुकदमा

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। कर्नलगंज स्थित एक निजी अस्पताल में पांच वर्षीय रजत की मौत मामले में डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है। उच्चाधिकारियों के आदेश पर रविवार को तीन डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत हार्ट में ब्लड की क्लाटिंग के चलते हुई। किन वजहों से ब्लड क्लाटिंग हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण अग्रिम जांच के लिए विसरा और हार्ट प्रिजर्व किया गया है। पूरा पड़ाइन दारागंज निवासी पूनम सोनकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तबीयत खराब होने पर उन्होंने 25 अगस्त की रात अपने पांच साल के बेटे रजत को मम्फोर्डगंज स्थित स्वाति हास्पिटल में भर्ती कराया था।

30 अगस्त को उसे डिस्चार्ज किया जाना था। आरोप है कि अस्पताल के बिल को लेकर उन्होंने ऐतराज जताया तो बच्चे को बिना पैसा दिए छोड़ने से इनकार कर दिया गया। इतना ही नहीं घरवालों को बच्चे से मिलने से रोक दिया गया। शाम को 7.30 बजे अस्पताल कर्मियों ने उन्हें बच्चे की मौत की खबर दी। रजत की मां की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में अस्पताल के डॉक्टर एलके त्रिपाठी सहित अन्य डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

ट्रेनों में चेकिंग, 77 यात्रियों से वसूला 42000 का जुर्माना

प्रयागराज। छिवकी से मानिकपुर तक शनिवार को रेलवे की टीम ने ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया। मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिमांशु शुक्ला के निर्देशन व सहायक वाणिज्य प्रबंधक दिनेश कुमार के निर्देशन में टीम ने ताप्ती एक्सप्रेस, बरौनी एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस और प्लेटफार्मों पर चेकिग की। 77 यात्रियों से अनधिकृत व अनियमित यात्रा व गंदगी फैलाने पर 42,600 रुपये जुर्माना वसूला गया। गाड़ी संख्या 13201 में खिलौने व मोबाइल एक्सेसरीज बेच रहे दो युवकों को पकड़कर आरपीएफ शंकरगढ़ को सौंपा गया।

पानी में तैरता हुआ मिला शव फाफामऊ।रविवार की सुबह एक युवक की लाश पानी मे तैरती मिली लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी।फाफामऊ पुलिस मौके पर पहुंच कर लाश को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।पता करने पर लक्ष्मी नगर फाफामऊ का आनंद कुमार भारतीय 30 वर्ष पुत्र राम गरीब गब्बर भारतीय के रूप मे हुई।परिजनों ने बताया कि करीब 2 दिन घर से निकला था। उसका कहीं पता नहीं चल रहा था।

अपनी घिनौनी भाषा के लिए पूरे देश से माफी मांगें महुआ मोइत्रा

गृह मंत्री का अपमान हर भारतीय का अपमान है : नन्दी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कड़ा विरोध किया है।

मंत्री नन्दी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की न केवल दूषित मानसिकता को उजागर करती है बल्कि यह टी.एम.सी के राजनीतिक पतन और घृणास्पद आचरण का स्पष्ट उदाहरण भी है।

महुआ मोइत्रा की टिप्पणी से लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान हुआ है और ऐसा बयान समाज

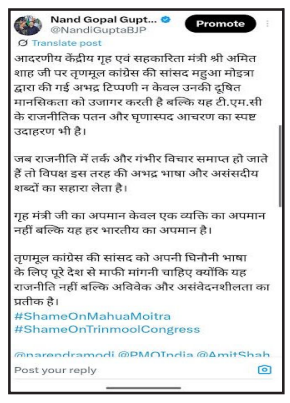

में नफरत फैलाने वाला है. साथ ही, इस तरह की भाषा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी खतरा बन सकती है।

मंत्री नन्दी ने कहा कि जब राजनीति में तर्क और गंभीर विचार समाप्त हो जाते हैं तो विपक्ष इस तरह की अभद्र भाषा और असंसदीय शब्दों का सहारा लेता है। गृह मंत्री का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि यह हर भारतीय का अपमान है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद को अपनी घिनौनी भाषा के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि यह राजनीति नहीं बल्कि अविवेक और असंवेदनशीलता का प्रतीक है।

आमजन में नई ऊर्जा का संचार करता है मन की बात

युवाओं के लिए एक नई उम्मीद और नया रास्ता दिखा रहा प्रतिभा सेतु

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सुनी मन की बात

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने रविवार को अपने प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के कीडगंज मंडल के बूथ संख्या 280 पूरावल्दी में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, व्यापारी भाइयों, समर्थकों एवं आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना।

मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक मार्गदर्शन सदैव नई ऊर्जा प्रदान करता है, जनसेवा के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण के कार्य में निरंतर जुटे रहने की प्रेरणा देता है।

मन की बात के 125वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक नई उम्मीद और नया रास्ता दिखाया। कहा कि 'प्रतिभा सेतु' नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया

है, जिसमें उन हज़ारों युवाओं का डेटा मौजूद है, जिन्होंने ऊझएण, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ और मेडिकल सर्विसेज़ जैसी कठिन परीक्षाओं के कई चरण पार किए, लेकिन अंतिम सूची में स्थान नहीं पा सके।

यह पोर्टल आज 10, 000 से भी अधिक मेधावी युवाओं की प्रतिभा का खज़ाना है। निजी कंपनियाँ इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इन युवाओं तक पहुँचकर उन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास सिर्फ़ एक योजना नहीं, बल्कि उन सपनों को नया आसमान देने की कोशिश है।

इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, कीडगंज मंडल अध्यक्ष कबीर जायसवाल, कीडगंज मंडल कोषाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष तिर्थेश्वर पुरी मिश्रा, देवेंद्र प्रताप सिंह, जितेंद्र चौरसिया, श्रीमती पूनम गुप्ता, पवन प्रताप सिंह, शलभ जायसवाल, मंडल मीडिया प्रभारी शिवराम सिंह, मंडल महामंत्री सनी सोनकर, श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, अश्विनी जायसवाल, श्रीमती रीता साहू, संजीव जायसवाल, सतीश चंद्र राव, बूथ अध्यक्ष महेंद्र पांडेय, सेक्टर संयोजक रमेश केसरवानी, पन्ना प्रमुख राजकुमार अग्रहरि, विशाल केसरवानी, प्रवीण कुमार साहू, मनोज कुमार, मनोज गुप्ता एवं गणमान्यजन मौजूद रहे।

प्रयागराज पहुंची शहीदी यात्रा गूंजा 'सत् श्री अकाल

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब धोबड़ी साहिब (असोम) से निकली शहीदी यात्रा रविवार को शहर पहुंची। शास्त्री पुल के रास्ते शहर में यात्रा के प्रवेश करते ही श्री गुरु सिंह सभा खुल्दाबाद, विश्व हिन्दू परिषद व प्रयाग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे तक यात्रा का स्वागत किया। फूलों से सुसज्जित रथ को देखते ही शीश झुकाकर सिख संगत सहित हजारों लोग 'जो बोले सो निहाल, सत् श्री अकाल का उद्घोष करते रहे। यात्रा अलोपीबाग चुंगी, सोहबतियाबाग, बालसन चौराहा, मेडिकल कॉलेज चौराहा, हनुमान मंदिर चौराहा होते हुए देर शाम सुभाष चौराहे पर पहुंची।

अलोपीबाग में तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जहां सिख संगतों के साथ हिन्दू-मुस्लिम भी गुरु की यात्रा का स्वागत पहुंचे थे। सुभाष चौराहे पर यात्रा पहुंचने के बाद गुरु साहब के जीवन व बलिदान की गाथा पर व्याख्यान हुआ। यहां से यात्रा पत्थर गिरजाघर, नगर निगम, नवाब युसूफ रोड, डीएसए पुल, रेलवे स्टेशन, प्रयाग होटल होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा खुल्दाबाद पहुंची। सभा के महामंत्री दिलजीत सिंह ने बताया कि रात्रि विश्राम के बाद एक सितंबर को यात्रा खुल्दाबाद सब्जी मंडी, हिम्मतगंज, चौफटका पुल, सुलेमसराय, मुंडेरा व गुरुद्वारा पूरामुफ्ती होते हुए बरेली के लिए प्रस्थान करेगी। स्वागत करने वालों में महापौर गणेश केसरवानी, विधायक हर्षवर्धन बाजपेई, सिख संगत अलोपीबाग के प्रधान सरदार परमजीत सिंह बग्गा, गुरदीप सिंह सारण, बलजीत सिंह कोहली, मनु चावला, प्रेमजीत गुजराल, लखविंदर सिंह, कुलदीप सिंह बग्गा, विहिप काशी प्रांत के अध्यक्ष केपी सिंह, उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, पार्षद साहिल अरोड़ा, रविंद्र मोहन गोयल आदि शामिल रहे।

सामूहिक दुष्कर्म का इनामी आरोपी पुलिस मुठभेड़ मे घायल

मंत्र भारत संवाददाता

फाफामऊ। कर्जन पुल के नीचे एक युवती से दुष्कर्म एवं मारपीट मामले में फरार आरोपित अनिल भारतीय उर्फ बरसाती पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली।

आरोपित ने सामूहिक दुष्कर्म की बात कबूली, 16 अगस्त को हुई थी घटना शनिवार को फाफामऊ पुलिस को सूचना मिली कि दुष्कर्म का इनामी आरोपी अनिल भारतीया उर्फ बरसाती मलाक हरहर मे दिखाई दिया है।फाफामऊ थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह मय फोर्स नव निर्माणाधीन सिक्सलेन पुल के पास घेरा बन्दी की पूर्वाह्न मे एक मोटर साईकिल बिना नम्बर की आती दिखाई पडी जिसे रुकने का इशारा पुलिस द्वारा किया गया पुलिस को देखते ही मोटर साइकिल की स्पीड बढा दी गई और फायरिंग शुरू कर दी पुलिस कुछ देर पीछा किया लेकिन फायरिंग न रुकने से आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी गोली चला दी जिससे भाग रहे अपराधी के पैर मे गोली लगी गोली लगते ही घायल होकर गिर पडा पुलिस तुरंत घायल को कब्जे में लिया जिसकी पहचान अनिल भारतीया उर्फ बरसाती के रूप हुई। मौके पर पिस्टल कारतूस व खोखा सहित बिना नम्बर की मोटर साइकिल बरामद कि गई है। घायल अनिल को इलाज हेतु अस्पताल मे भर्ती कराया है।आरोपी के ऊपर पूर्व मे भी अपराधिक केश दर्ज है।इस पर 25000/ हजार का इनाम घोषित किया गया था।

हाईकोर्ट के निर्देश पर ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया

मंत्र भारत संवाददाता

थरवई (प्रयागराज)। फूलपुर तहसील क्षेत्र के देवापुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने शनिवार को हटा दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी फूलपुर दिग्विजय सिंह, तहसीलदार सुरेश कुमार शुक्ला और नायब तहसीलदार नवल किशोर शुक्ला के नेतृत्व में की गई।

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए थरवई पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। ग्राम समाज की जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा होने की शिकायतें मिल रही थीं। ग्रामीणों ने बताया कि कब्जा हटने से गांव में राहत का माहौल है।प्रशासनिक अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ग्राम समाज की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला पदाधिकारियों का मनोनयन

व्यापारियों के बल पर ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा : कमलेश चंद्र

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला पदाधिकारियों का मनोनयन कार्यक्रम मुंशी राम प्रसाद की बगिया मुट्ठीगंज में किया गया। इस अवसर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री कमलेश चंद्र केसरवानी ने मनोनीत हुए सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देकर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का व्यापारी समाज एकजुट होकर व्यापारी समाज के हित कि लड़ाई लड़ रहा है और कहा कि व्यापारी समाज के बल पर ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सोनू ने करते हुए सभी नवनियुक्त मनोनीत पदाधिकारी को बधाई दी मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी सोनू के नेतृत्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार केसरवानी, उपाध्यक्ष रोशनी अग्रवाल, राजेश गुप्ता, प्रयागराज जिले के महामंत्री गौरव गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमित कुमार केसरवानी, कमलेश केशरवानी किशन चन्द्र जायसवाल, शत्रुघ्न जायसवाल योगेंद्र बिना शिवलाल केसरवानी, मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता राजेश केसरवानी एवं जिला अध्यक्ष जमुना पार राजेंद्र गुप्ता एवं उपाध्यक्ष शशि शेखर श्रीवास्तव को मनोनीत किया गया और मनोनीत किए गए सभी पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए संकल्प दिलाया गया।

स्कूल से छुट्टी, सोशल मीडिया पर ड्यूटी

रील बनाना पड़ा भारी, बिना सूचना के 75 दिन से गायब शिक्षिका सस्पेंड

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश में अलीगढ़ जिले के महुआखेड़ा स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका चैताली वार्ष्णेय पिछले 75 दिनों से स्कूल नहीं आ रहीं थीं। उन्होंने ना तो स्कूल को कोई सूचना दी और ना ही शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए नोटिसों का कोई जवाब दिया। वहीं, इस दौरान वह सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव पाई गईं, जहां वह रील और पारिवारिक फोटो शेयर करती रहीं। इस लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने शिक्षिका को 29 अगस्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनसे लिखित रूप में जवाब मांगा गया है कि वे इतने दिन तक बिना बताए क्यों गायब रहीं।

चैताली वार्ष्णेय आखिरी बार 15 जून को स्कूल आई थीं। इसके बाद से वे बिना सूचना के स्कूल नहीं आईं। शिक्षा विभाग ने उन्हें कई बार पत्र भेजकर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब अधिकारियों ने जांच की, तो पता चला कि चैताली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और रील्स बना रही हैं। इसके बाद बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

चैताली ने हाल ही में 6 दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। यह देखकर विभाग ने माना कि शिक्षिका जानबूझकर ड्यूटी से दूर हैं।

चैताली के पति नूतन प्रकाश ने विभाग की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि चैताली बीमार चल रही हैं। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वे अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखेंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे।

बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि चैताली वार्ष्णेय को लगातार अनुपस्थित रहने और नोटिस का जवाब न देने पर 29 अगस्त को सस्पेंड किया गया। उनसे लिखित जवाब मांगा गया है, जिसे उन्हें जल्द ही देना होगा। मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है।

गले पर गहरे निशान-दुष्कर्म की आशंका

प्रदेश के झांसी में महिला का घर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, गांव में दहशत का माहौल

लखनऊ **(एजेंसी)**। जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के बरौरी गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव की रहने वाली 42 वर्षीय ऊषा रैकवार का शव उसके घर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। गले पर गहरे निशान और बिखरे कपड़े इस घटना को एक बर्बर अपराध की ओर इशारा कर रहे हैं।

परिवार और ग्रामीणों के अनुसार, महिला अकेली रहती थी, क्योंकि उसका पति और दोनों बेटे काम के सिलसिले में बाहर हैं। शुक्रवार सुबह जब काम पर जाने वाले मजदूरों और पड़ोसियों ने ऊषा को आवाज दी और कोई उत्तर नहीं मिला, तो संदेह हुआ। दरवाजा बंद देख, परिजनों को सूचना दी गई। महिला का भतीजा जब दीवार फांदकर अंदर पहुंचा, तो देखा कि

ऊषा मृत पड़ी थी। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मऊरानीपुर पुलिस, सीओ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी।

गांव में इस वीभत्स घटना से सनसनी फैल गई है। महिला के शांत स्वभाव और किसी से विवाद न होने की बात कहकर ग्रामीण भी सदमे में हैं। भारी संख्या में लोग महिला के घर के बाहर जमा हो गए हैं। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मृतका के मोबाइल रिकॉर्ड, घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट से मौत की असली वजह स्पष्ट होगी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह बेहद गंभीर अपराध है और जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। कई लोगों से पूछताछ जारी है और कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। फिलहाल, गांव में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि माहौल शांत रहे।

सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी 'राधा अष्टमी' की बधाई

कहा- श्री राधा रानी जी की कृपा का संचार सभी के जीवन में हो

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने रविवार को प्रदेशवासियों को 'राधा अष्टमी' पर्व की बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक 'एक्स' खाते पर एक पोस्ट में कहा, 'पावन पर्व 'राधा अष्टमी' की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! निष्काम प्रेम, करुणा व भक्ति की साक्षात स्वरूप श्री राधा रानी जी की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का संचार हो, यही प्रार्थना है। जय श्री राधे!'

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा, 'पावन पर्व राधा अष्टमी की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं!' मौर्य ने कहा, 'प्रेम, भक्ति और करुणा की अविनाशी ज्योति श्री राधारानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा से हम सभी के जीवन में शांति, सुख एवं समृद्धि का प्रवाह बना रहे। जय श्री राधे!'

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'आप सभी को पावन पर्व राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।' अधिकारियों के अनुसार मथुरा बरसाना स्थित श्री राधारानी मंदिर में 30 अगस्त से शुरू हुए इस दो दिवसीय उत्सव में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। पर्व का मुख्य आयोजन आज सुबह से ही शुरू हो गया है।

प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का मकान जमींदोज, सेकंड भर में भरभराकर गिरी इमारत

सीहोर **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का सीहोर स्थित मकान रविवार को अचानक ढह गया। यह मकान लंबे समय से जर्जर हालत में था और खाली पड़ा हुआ था। गनीमत रही कि इमारत में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, सीहोर के नमक चौराहा इलाके में पंडित प्रदीप मिश्रा का

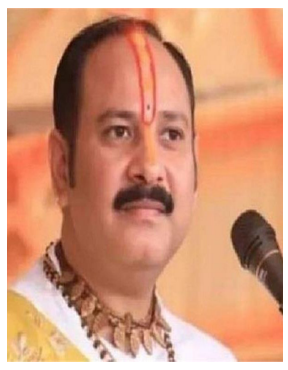

यह पुराना मकान स्थित है। रविवार को इसका एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और पूरी तरह जमींदोज हो गया। सीहोर कलेक्टर बालगुरु ने बारिश के पहले जिले में जर्जर भवनों की पहचान कर उनके मालिकों को नोटिस देने के निर्देश जारी किए थे। इसी क्रम में नगर पालिका ने प्रदीप मिश्रा के मकान को भी असुरक्षित घोषित कर दिया था। अतिक्रमण प्रभारी तिलक खाती ने बताया कि मकान को नोटिस देकर पहले ही खाली करा लिया गया था।

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मूल रूप से सीहोर के ही रहने वाले हैं। शहर के नमक चौराहा क्षेत्र में उनका यह पैतृक मकान था, जो लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था। रविवार को यह जर्जर इमारत गिरने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल जरूर बना, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

कानपुर देहात में 3 युवकों की जहरीली गैस के कारण मौत, सीवर टैंक की सफाई करने गए थे तीनों

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के कानपुर देहात के जिले के अकबरपुर क्षेत्र में एक नवनिर्मित सीवर टैंक में जहरीली गैस के प्रभाव से तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। कानपुर देहात जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरविंद मिश्रा ने पुष्टि की कि नवनिर्मित सीवर टैंक में जहरीली गैस के कारण तीन लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है और घटना की जांच जारी है। अकबरपुर थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब बिगाही गांव निवासी मजदूर मुबीन (26) शटरिंग हटाने के लिए करीब 10 फुट गहरे सीवर टैंक में उतरा, लेकिन जहरीली गैस के प्रभाव से उसका दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रभारी ने बताया कि मुबीन की हालत बिगड़ती देख मकान मालिक सुरेंद्र गुप्ता उर्फ अमन (22) और साथी मजदूर सर्वेश कुशवाहा (32) उसे बचाने के लिए टैंक में उतरे, लेकिन वे भी जहरीली गैस के प्रभाव में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। मुबीन का भाई इसरार (22) भी उन्हें बचाने के लिए टैंक में कूद गया, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल सका। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चारों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मुबीन, सुरेंद्र और सर्वेश को मृत घोषित कर दिया। इसरार की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतरे थे।

शाह पर 'सिर काटने' वाले बयान पर महुआ मोइत्रा फंसीं, छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज

रायपुर **(एजेंसी)**। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 'आपत्तिजनक' टिप्पणी की थी। इसी सिलसिले में अब उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक एफआईआर दर्ज की गई है। यहां एक स्थानीय निवासी ने मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप) के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई भाजपा नेताओं ने मोइत्रा की टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने तृणमूल नेता के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर कहा था कि भारत में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने में विफल रहने के लिए अमित शाह का 'सिर काट' देना चाहिए। उन्होंने यह कथित बयान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा ने मोइत्रा की कड़ी आलोचना की थी।

ओडिशा में ईडी का बड़ा एक्शन : करोड़ों के बैंक घोटाले में जब्त हुईं 10 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1, 396 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में ओडिशा के एक व्यवसायी और उसकी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी के बाद एक पोर्श, एक मर्सिडीज, एक मिनी कूपर और एक बीएमडब्ल्यू समेत 10 से अधिक लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में करोड़ों रुपये की लग्जरी कारें, आभूषण और नकदी जब्त की। छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 10 लग्जरी कारें और 3 सुपरबाइक जब्त कीं, जिनमें एक पोर्श कायेन, मर्सिडीज-बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू एक्स7, ऑडी ए3, मिनी कूपर और एक होंडा गोल्ड विंग मोटरसाइकिल शामिल हैं। ईडी ने 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण, 13 लाख रुपये

नकद, अचल संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए और डैश के दो लॉकर भी जब्त कर लिए। अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) व अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) और उनके प्रबंध निदेशक (एमडी) शक्ति रंजन दाश के भुवनेश्वर में स्थित परिसरों पर शनिवार को छापेमारी की गई।

हिमाचल प्रदेश में स्थित इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (आईटीसीओएल) नामक कंपनी के खिलाफ दर्ज कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में यह कार्रवाई की गई। धन शोधन का यह मामला आईटीसीओएल और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी के निदेशकों ने विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ मिलकर बैंकों के एक संघ से लिए गए ऋणों की हेराफेरी की।

ईडी के अनुसार आईटीसीओएल और उसकी संबंधित फर्जी कंपनी ने एएमपीएल के बैंक खातों में 59.80 करोड़ रुपये डलवाए। आरोप है कि दाश ने ओडिशा में खनन गतिविधियों के लिए इस पैसे का उपयोग करने में 'जानबूझकर' आईटीसीओएल के प्रवर्तक राकेश कुमार शर्मा की सहायता की। ईडी के बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान दाश और उसके स्वामित्व वाली कंपनियों से संबंधित 10 लग्जरी वाहन और तीन सुपर बाइक जब्त की गईं।

जब्त वाहनों में एक पोर्श कायेन, एक मर्सिडीज-बेंज जीएलसी, एक बीएमडब्ल्यू एक्स7, एक ऑडी ए3, एक मिनी कूपर और एक होंडा गोल्ड विंग बाइक शामिल हैं, जिनकी कीमत सात करोड़ रुपये से अधिक है। बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान 13 लाख रुपये नकद और 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण भी जब्त किए गए हैं, जबकि दाश के दो लॉकर से लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।

बिहार का लाल श्रीनगर में शहीद, 3 महीने पहले हुई थी शादी, शोक में डूबा गांव

पटना **(एजेंसी)**। बिहार के सारण का आर्मी जवान श्रीनगर में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। वहीं अब उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

शहीद जवान छोटू शर्मा सारण के दरियापुर थाना क्षेत्र के बेला शर्मा टोला गांव के निवासी थे। मिली जानकारी के अनुसार, जवान के सिर में गोली लगी थी। सेना के अधिकारियों ने शनिवार देर शाम परिजनों को जवान छोटू के शहीद होने की सूचना दी। हालांकि, उन्होंने गोली चलने की वजह स्पष्ट नहीं बताई है। बताया जा रहा है कि शहीद जवान की शादी इसी साल 9 मई को हुई थी। परिजनों के अनुसार, शादी के अगले ही दिन छोटू शर्मा को 'ऑपरेशन सिंदूर' की खबर मिली थी, जिसके बाद वे अपनी ड्यूटी लौट गए। परिजनों ने बताया कि छोटू 4 बहनों में सबसे छोटा भाई था। पिता की मौत हो चुकी थी। छोटू 2017 में सेना में भर्ती हुए थे, जिसके बाद घर की स्थिति में सुधार हुआ था। वह अपने परिवार के एकमात्र सरकारी नौकरी वाले शख्स थे। उनकी शहादत के बाद पूरा परिवार गमगीन है।

मुख्यमंत्री मोहन बोले- राहुल गांधी को नाना-नानी के पास चले जाना चाहिए, उनको इस जगत में रहने का अधिकार नहीं

मुरैना **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मुरैना दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर गलत बयान देते हैं। अगर उन्हें इतनी परेशानी है, तो अपने नाना-दादी और पिता के पास चले जाना चाहिए। इस जगत में रहने का उन्हें कोई हक नहीं है। दरअसल सीएम यादव मुरैना में हाइड्रोजन यूनिट के भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया।

सीएम ने कहा कि राहुल गांधी तरह-तरह के प्रपंच रचते हैं। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल कर रहे हैं। यदि उन्हें शंका थी तो सर्जिकल स्ट्राइक के समय वहां चले जाना चाहिए था। बम के नीचे खड़े होकर सब पता चल जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए, जिन्होंने विपक्ष और मंत्रियों के साथ मिलकर लोकतंत्र की मर्यादा निभाई थी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिले में 101 हेक्टेयर का एक नया औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पिपरसेवा में 157.5 करोड़ की लागत से 500 मेगावाट का सोलर प्लांट भी 2030 तक तैयार होगा। उन्होंने कहा कि कभी मुरैना-चंबल क्षेत्र में उद्योगपति आना नहीं चाहते थे, क्योंकि कांग्रेसियों ने यहां डाकुओं को जमीन दे रखी थी। लेकिन अब समय बदल रहा है और बड़े उद्योगपति यहां निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुरैना में करीब 300 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है और यहां शनि लोक भी बनाया जाएगा। भूमिपूजन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव शनि मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। इसके बाद वे पोरसा पहुंचकर ग्राम रजौधा में सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण और आसमानी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। यह मंदिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पैतृक गांव में स्थित है।

मोहन भागवत की तारीफ, मोदी-योगी पर वार! सपा सांसद अफ़ज़ाल अंसारी ने पूर्वी यूपी में छेड़ी नई सियासी जंग

गाज़ीपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अफ़ज़ाल अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने एकता का आह्वान किया था और नफ़रत की राजनीति को नकारा था, की प्रशंसा करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। साथ ही, अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर सामाजिक सद्भाव को नष्ट करने और आम नागरिकों के संघर्षों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

गाज़ीपुर में ज़िले की बिजली आपूर्ति पर एक समीक्षा बैठक के बाद बोलते हुए, अंसारी ने भागवत की एकता और भाईचारे पर हालिया टिप्पणी का स्वागत किया। अंसारी ने कहा, 'मोहन भागवत ने कहा कि देश को एकता और भाईचारे की ज़रूरत है और नफ़रत का कारोबार बंद होना चाहिए। यह स्वागत योग्य है और मैं उनकी सराहना करता हूँ। अन्य धार्मिक नेताओं को भी इससे सीख लेनी चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया में आरएसएस से बड़ा कोई संगठन नहीं है। अगर इसके प्रमुख कहते हैं कि हर मंदिर और तीर्थस्थल में शिवलिंग ढूँढ़ने से देश कमज़ोर होगा, तो इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं उनके शब्दों का स्वागत करता हूँ और दूसरों को भी उनके सकारात्मक संदेश का स्वागत करना चाहिए।'

इस्लाम सदियों से भारत का अभिन्न अंग रहा है

सपा सांसद ने ज़ोर देकर कहा कि इस्लाम सदियों से भारत का अभिन्न अंग रहा है, इस तथ्य को भागवत ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, 'इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, यह भारत में बहुत लंबे समय से है और मोहन भागवत ने इस सच्चाई को स्पष्ट कर दिया है।'

मोदी और योगी 'बिना परिवार वाले'

हालाँकि, जब अंसारी ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उनके निजी जीवन को लेकर निशाना साधा, तो सुर तुरंत राजनीति की ओर मुड़ गए। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में बैठे आका का कोई परिवार नहीं है और उत्तर प्रदेश में बैठे आका का भी कोई परिवार नहीं है।' इस पर, अंसारी के बगल में बैठे सपा विधायक जय किशन साहू ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'वे कोशिश कर रहे हैं।' अंसारी ने तुरंत जवाब दिया, 'मैं एक लाइसेंस प्राप्त परिवार की बात कर रहा हूँ, बिना लाइसेंस वाले परिवार की नहीं। यह उनका दुर्भाग्य है कि ईश्वर ने उन्हें संतान का आशीर्वाद नहीं दिया।' अंसारी ने आगे कहा कि मोदी और योगी 'बिना परिवार वाले' हैं, यहाँ तक कि अपनी सात पीढ़ियों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने अपने व्यंग्य को और तीखा बनाने के लिए चाणक्य का भी ज़िक्र किया।

राजनीतिक मोर्चे पर, अंसारी ने बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 'अवध और मगध' वाले बयान की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार बिहार में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे।'

बीसीसीआई को 450 करोड़ के स्पॉन्सरशिप मिलने की उम्मीद?

ड्रीम 11 से भी ज्यादा बड़ी डील मिलने की योजना

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्पॉन्सर के रूप में ड्रीम 11 के जाने के बाद टीम से जुड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नीति साफ कर दी है। ड्रीम 11 को संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित होने के बाद अपना अनुबंध समय से पहले ही खत्म करना पड़ा। इस हालात में बोर्ड को एक मुश्किल में डाल दिया है। क्योंकि एशिया कप 2025 की शुरुआत से पहले एक स्पॉन्सर ढूंढना और पुरुष टीम की जर्सी छपवाना मुश्लि हो सकता है।

वहीं एनडीटीवी सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई 2025-28 की अवधि के लिए एक नए स्पॉन्सर को जोड़ने की कोशिश कर रहा है जिसकी प्रायोजन राशि लगभग 450 करोड़ रुपये होगी।

ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ तीन साल का करार किया था। इसमें ब्रांड बीसीसीआई को कॉन्ट्रैक्ट के दौरान 358 करोड़ रुपये का भुगतान करता। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर की तारीख से लगभग दो साल बाद ये डील को खत्म करना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई अब 2025 से 2028 तक 140 मैचों के लिए एक स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये करार ड्रीम 11 द्वारा बोर्ड को दी गई राशि की तुलना में बेहतर होगा। प्रायोजन घरेलू और विदेश द्विपक्षीय मैचों के साथ-साथ एशियाई क्रिकेट परिषद और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित बहु-टीम टूर्नामेंटों के लिए होगा।

बीसीसीआई ने द्विपक्षीय मैच के लिए 3.5 करोड़ रुपये और आईसीसी और एसीसी मैचों के लिए 1.5 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। जो ड्रीम 11 से ज्यादा है लेकिन बायजू से कम है। जहां तक एशिया कप का सवाल है तो बोर्ड महाद्विपीय टूर्नामिंट की शुरुआत से पहले एक शर्ट प्रायोजक पाने की कोशिश कर रहा है। समय कम होने के कारण थोड़ी देरी हो सकती है। बोर्ड को विश्वास है कि वह 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला वर्ल्ड कप से पहले एक नई यूनिट को सील कर लेगा।

जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत : रिजर्व बैंक गवर्नर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री जन-धन योजना को देश की वृद्धि दर बढ़ाने में मददगार करार देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शनिवार को कहा कि देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने यह बात ऐसे वक्त कही जब देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.80 प्रतिशत रही है।

अमेरिका के भारी शुल्क लगाए जाने से पहले की पांच तिमाहियों में यह सबसे अधिक है। मल्होत्रा ने इंदौर के रंगवासा गांव में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय समावेशन अभियान संतृप्ति शिविर में कहा कि 11 साल पहले केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत वित्तीय समावेशन का अभियान शुरू किया था, जिससे पूरे देश में विकास हो रहा है।

उन्होंने कहा, आज दुनिया के (सबसे) विकसित देशों में भारत की गिनती पांचवें नंबर पर हो रही है और बहुत जल्द ही भारत (इस सूची में) तीसरा (सबसे) बड़ा देश बनने वाला है।

मल्होत्रा ने कहा कि देश की विकास यात्रा में हर स्थान और तबके के लोगों को सहभागी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं और उन्हें बचत, पेंशन, बीमा, ऋण तथा अन्य सेवाएं देनी शुरू की गईं।

रिजर्व बैंक गवर्नर ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना से जुड़े खाताधारक 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' प्रक्रिया के तहत अपना ब्योरा तय अवधि में अद्यतन कराएं, ताकि खाते के दुरुपयोग की आशंकाओं को समाप्त किया जा सके।

मल्होत्रा ने कहा कि आम लोग अपनी डिजिटल साक्षरता और वित्तीय जागरूकता बढ़ाएं ताकि वे बैंकिंग धोखाधड़ी से बच सकें। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वह डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई का अधिक से अधिक उपयोग करे। गवर्नर ने वित्तीय समावेशन अभियान में महिलाओं की अहम भागीदारी पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आधी आबादी देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने बताया कि फिलहाल देश के लगभग सभी गांवों के पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकों की शाखाओं या 'बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट' के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकों के साथ मिलकर एक जुलाई से वित्तीय समावेशन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जो 30 सितंबर तक चलेगा।

इस अभियान में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के नये खाते खोलना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लोगों के नामांकन और खाताधारकों के केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सीएस शेट्टी भी मौजूद थे।

राहुल द्रविड़ के बाद संजू सैमसन की होगी छुट्टी! बंट गई राजस्थान रॉयल्स

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने भले ही राहुल द्रविड़ से अचानक किनारा कर लिया हो लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला नहीं है। इसे लेकर कुछ समय से चर्चा चल रही थी। आईपीएल 2025 में फ्रेंचाइजी के 9वें नंबर र रहने के बाद द्रविड़ का पद पर बने रहना मुश्किल था।

भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद राहुल द्रविड़ फिर से रॉयल्स से जुड़े थे। ऐसे में टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द्रविड़ की विदाई ऐसे समय पर हुई जब फ्रेंचाइजी और संजू सैमसन के बीच कुछ ठीक नहीं था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सैमसन भी राजस्थान रॉयल्स से विदा हो जाएंगे? ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि फ्रेंचाइजी 3 धड़े में बंटी हुई है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार राहुल द्रविड़ और रॉयल्स प्रबंधन के बीच जुलाई से ही बातचीत चल रही थी, जब लंदन में आईपीएल 2025 के प्रदर्शन की समीक्षा हो रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें टीम से जोड़े रखने के इच्छुक मनोज बडाले ने उन्हें एक अलग पद की पेशकश की थी। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को अपनी विज्ञप्ति में इसका जिक्र भी किया था, लेकिन द्रविड़ ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सैमसन अपनी चोट के अलावा आईपीएल 2025 के दौरान राजस्थान रॉयल्स के कैंप में चली रही चीजों से नाखुश थे। हालांकि, कप्तान की नाराजगी के लिए सिर्फ द्रविड़ ही जिम्मेदार नहीं हो सकते। माना जा रहा है कि द्रविड़ और सैमसन के बीच कोच और कप्तान के बीच होने वाली आम, सामान्य और नियमित असहमतियां ही थीं। ऐसा नहीं था कि दोनों का रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ गया था।

वहीं टीम को लेकर चर्चाओं से पता चलता है कि फ्रेंचाइजी में तीन अलग-अलग विचारधाराएं चल रही थीं। एक गुट रियान पराग के पक्ष में था, जिन्होंने कुछ मैचों में टीम की कप्तानी की। दूसरे ने यशस्वी जायसवाल को भविष्य का कप्तान बताया।

बीसीसीआई ने धोनी को दिया बड़ा ऑफर तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने धोनी पर कसा तंज

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। टीम इंडिया इन दिनों एशिया कप 2025 की तैयारी में जुटी है। इसके बाद टीम इंडिया को अगले साल टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि, बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूर्व कप्तान और बल्लेबाज एमएस धोनी को टीम इंडिया का मेंटॉर बनने का ऑफर दिया है। हालांकि, बीसीसीआई की तरफ से इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने धोनी पर तंज कसा है।

तिवारी ने कहा कि, ये तो समय ही बताए, उनको ऑफर दिया है वो फोन उठाए हैं। जहां तक मुझे पता है उनसे फोन पर बात करना मुश्किल है। मैसेज की रिप्लाई भी कम ही मिलता है। बहुत सारे प्लेयर ऐसा कह चुके हैं वो अगर मैसेज पढ़ते हैं तो क्या रिप्लाई करेंगे। मैसेज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। उन्हें मेंटॉरशिप दी जा रही है तो वह इसे स्वीकार करते हैं या नहीं ये तो समय ही बताएगा। वह क्या इम्पैक्ट लेकर आएंगे ये बताना मुश्किल है। पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा कि, बतौर कप्तान और प्लेयर उनका जो अनुभव रहा है वह टीम के काम आएगा। भारतीय टीम के जो नए सितारे उभरकर आ रहे हैं कहीं न कहीं उनकी बहुत इज्जत करते हैं उनकी बात सुनेंगे। एमएस धोनी और हेड कोच गौतम गंभीर की जो जोड़ी बनेगी वह भी देखने वाली होगी।

अजुल गाने पर बढ़ा विवाद तो गुरु रंधावा ने आलोचकों के लिए शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

मशहूर गायक गुरु रंधावा का हाल ही में रिलीज हुआ गाना 'अजुल' विवादों में घिर गया है। जहां एक तरफ यह गाना लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि गाने में स्कूली छात्राओं को अनुचित तरीके से दिखाया गया है।

इस गाने के म्यूजिक वीडियो में गुरु रंधावा एक फ़ोटोग्राफ़ी शिक्षक की भूमिका में हैं, जो एक लड़कियों के स्कूल में तस्वीरें लेने जाते हैं। वीडियो में छात्रा की भूमिका निभा रही अभिनेत्री अंशिका पांडे एक डांस सीक्वेंस करती हैं, जिससे गुरु का किरदार मंत्रमुग्ध हो जाता है। आलोचकों का कहना है कि यह दृश्य और वीडियो का कॉन्सेप्ट आपत्तिजनक है।

विवाद बढ़ने के बाद, गुरु रंधावा ने सीधे तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ पोस्ट शेयर किए। उन्होंने पंजाबी में लिखा, 'जदो मैं सब नू खुश करने लगा, दुखी हो गया। अज्ज मैं खुद खुश हूं, सब दुखी हो गए।' (जब मैंने सबको खुश करने की कोशिश की, तो मैं दुखी था। आज, जब मैं खुद खुश हूं, तो बाकी सब दुखी हैं।) इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में गाने की सफलता के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने लिखा, 'अजुल इज अजुलिंग। जब भगवान आपके साथ होते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं।' यह गाना गुरु रंधावा ने ही लिखा और कंपोज किया है, जिसके अतिरिक्त बोल गुरजीत गिल ने लिखे हैं।

दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगदीशन करेगा साउथ जोन टीम की कप्तानी, तिलक को जाना दुबई

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केरल के बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को नॉर्थ जोन के खिलाफ चार सितंबर से बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल के लिए रविवार को तिलक वर्मा की जगह दक्षिण क्षेत्र का कप्तान नियुक्त किया गया है। तिलक वर्मा को टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है और इसलिए वह आगे दलीप ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। 4 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों को दुबई पहुंचना है, जबकि दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल भी इसी दिन से शुरू होने हैं।

तिलक वर्मा के साथ अजहरुद्दीन टीम के उपकप्तान थे और अब उप-कप्तान की भूमिका तमिलनाडु के एन जगदीशन को सौंप दी गई है। तमिलनाडु के बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर भी सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह अभी हाथ की चोट से उबर रहे हैं। पुडुचेरी के अंकित शर्मा और आंध्र के शेख रशीद को दलीप ट्रॉफी के अंतिम चार के मैचों के लिए दक्षिण क्षेत्र की टीम में शामिल किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को पहले स्टैंडबाय में रखा गया था। अंकित बाएं हाथ के स्पिनर हैं जिन्होंने 68 प्रथम श्रेणी मैचों में 168 विकेट लिए हैं। रशीद शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के 19 मैच में 1204 रन बनाए हैं। कई अनुभवा खिलाड़ी इस टीम के पास हैं। हालांकि, नॉर्थ जोन के पास भी अच्छे खिलाड़ियों की भरमार है जिससे ये मुकाबला और भी ज्यादा खास हो जाएगा। दोनों क्वार्टर फाइनल मैच ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में अब सेमीफाइनल मैच ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे।

बड़े स्थानीय बाजार की बदौलत भारतीय उद्योग जगत सहज स्थिति में : गोयल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय उद्योग जगत 1.4 अरब लोगों के घरेलू बाजार के कारण आरामदायक, सहज स्थिति में है और उन्हें वैश्विक स्तर पर अवसर तलाशने की जरूरत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर उच्च अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को लेकर गहरी चिंताओं के बीच गोयल ने यह टिप्पणी की। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से किसी भी नकारात्मक दलील से प्रभावित न होने को कहा और याद दिलाया कि जून में देश की जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई है।

गोयल ने भरोसा जताया कि इस साल कुल निर्यात बढ़ेगा और यह भी बताया कि अमेरिका को होने वाले 87 अरब डॉलर के निर्यात में 46 अरब डॉलर से ज्यादा पर शुल्क बढ़ाने का कोई असर नहीं है। गोयल ने कहा कि शुक्रवार को आए वृद्धि दर के आंकड़ों ने सरकार में किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अर्थशास्त्रियों और मीडिया के कुछ वर्गों जैसे नकारात्मक और निराशावादियों के लिए एक जोरदार जवाब है।

गोयल ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान पीटीआई वीडियोज को बताया, भारत लचीलेपन और आत्मविश्वास से भरा है और अगले 22 वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने के लिए उत्सुक है।

भारत आगे भी इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। हमारा निर्यात बढ़ता रहेगा, हम इस साल पिछले साल से ज्यादा निर्यात करेंगे और भविष्य बेहद उज्ज्वल है। उद्योग निकाय सीआईआई के कार्यक्रम भारत-यूएई व्यापार संवाद में गोयल ने स्वीकार किया कि घरेलू बाजार विकास के सबसे बड़े चालकों में से एक है और उन्होंने उद्योग की भूमिका पर भी खुलकर बात की।

उन्होंने कहा, मुझे अक्सर लगता है कि 1.4 अरब का विशाल घरेलू बाजार एक तरह से आरामदायक क्षेत्र बन गया है। हमारे व्यवसाय यहां अच्छा मुनाफा कमाते हैं और दुनिया भर में अवसरों की तलाश में बाहर नहीं निकलते।

गोयल ने कहा कि भारतीय उद्योग बहुत कम मूल्यवर्धन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें व्यवसायों और लोगों, दोनों पर भरोसा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर किसी भी बाधा का समाधान करने के लिए तैयार है।

हीरो एशिया कप 2025 राजगीर : दूसरे दिन गोलों की बरसात और पूल-बी में उलटफेर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। हीरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 का दूसरा दिन रोमांच से भरपूर रहा, जब पूल-बी के मुकाबले सुर्खियों में छा गए। दर्शकों ने दो यादगार मैच देखे – पहला जबरदस्त गोलों की बारिश वाला और दूसरा एक रोमांचक रणनीतिक जंग जो अंतिम क्षणों तक संघर्षपूर्ण रहा।

बांग्लादेश ने चीनी ताइपेई पर 8-3 की शानदार जीत दर्ज की, लेकिन स्कोरलाइन पूरी कहानी नहीं बताती। हाफ-टाइम तक मुकाबला 2-2 पर बराबरी पर था और चीनी ताइपेई ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाया। लेकिन दूसरे हाफ़ में बांग्लादेश ने आक्रामक खेल का तूफ़ान ला दिया और छह गोल दागकर टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत हासिल कर ली।

दिन का दूसरा मुकाबला पूल-बी की एक क्लासिक भिड़ंत थी, जिसमें कोरिया और मलेशिया आमने-सामने थे। हाफ-टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबरी पर था। लेकिन दूसरे हाफ़ में मलेशिया ने अपने मौक़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए तीन गोल दागे और 4-1 से बड़ी जीत दर्ज की। यह नतीजा पूल-बी की अंक तालिका के लिए अहम साबित हो सकता है, क्योंकि मलेशिया ने खुद को गंभीर दावेदार के रूप में पेश किया।

पवन सिंह ने अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने पर मांगी सार्वजनिक माफी, एक्ट्रेस ने किया भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अपनी सह-कलाकार अंजलि राघव से माफ़ी मांगी है, क्योंकि उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया है। राघव ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में सिंह पर बिना सहमति के उन्हें छूने का आरोप लगाया था। अब अंजलि ने अपने अनुचित व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी है। भोजपुरी अभिनेता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हिंदी में एक नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई, तो मुझे बुरा लगा।' हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान, पवन ने अंजलि की कमर को बार-बार छुआ और दावा किया कि कुछ फँस गया है, जबकि अंजलि असहज दिख रही थीं। इस घटना की काफी आलोचना हुई और अभिनेता को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी।

शनिवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर पवन ने कहा कि अंजलि के प्रति उनका कोई गलत इरादा नहीं था। उन्होंने हिंदी में एक माफ़ीनामा लिखा, जिसमें लिखा था, 'अंजलि जी, व्यवस्थित शेड्यूल के कारण मैंने आपको लाइव नहीं देखा। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई, तो मुझे बुरा लगा।' उन्होंने आगे कहा, 'मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इरादा नहीं था क्योंकि हमलोग कलाकार हैं। इसके लिए बकवास, अगर आपको हमारी कोई भी ब्यावाहर से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं शमा प्राथी हूं।'

हरियाणवी संगीत वीडियो में अपनी उपस्थिति के लिए मशहूर अंजलि राघव ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दो वीडियो साझा किए और बताया कि लखनऊ कार्यक्रम में क्या हुआ। उन्होंने घटना को याद करते हुए कहा, 'मैं दो दिनों से बहुत परेशान हूं। मुझे डीएम जारी रखें, जो लखनऊ वाला हादसा हुआ, उसमें मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं; कुछ मीम्स पर लिख रहे हैं।' तो हंस रही थी, मजा ले रही थी।' क्या पब्लिक में मुझे टच करके जाने से मुझे खुशी होगी?' एक वीडियो में उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। कलाकार हूं, तो नई चीज ट्राई करने का मन करता है, लेकिन मैं अपने परिवार और हरियाणा में खुश हूं।' अंजलि ने इंस्टाग्राम पर पवन की माफ़ी का जवाब देते हुए अपनी स्टोरी पर उनकी माफ़ी दोबारा पोस्ट की और लिखा, पवन सिंह जी ने अपनी गलती मान ली और माफ़ी मांग ली। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती।

पवित्र रिश्ता में अंकिता लोखंडे की बहन 'वर्षा' उर्फ प्रिया मराठे की मौत, 38 साल की उम्र में हारी जिंदगी की जंग

मराठी और हिंदी टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री प्रिया मराठे कैंसर से जंग हार गईं। प्रिया मराठे ने महज 38 साल की उम्र में अपने आवास पर अंतिम सांस ली और उनके निधन से मराठी मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पिछले कुछ दिनों से प्रिया मराठे मुंबई के एक निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रही थीं। हालाँकि, कैंसर से उनकी जंग नाकाम रही और रविवार, 31 अगस्त को सुबह 4 बजे मीरा रोड स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया। शाम 4 बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

एूदिब म्दहूगहले ंत्दै ूर्पे ्

प्रिया मराठे को कुछ साल पहले कैंसर का पता चला था। इस बीच, वह इस गंभीर बीमारी से उबर चुकी थीं। हालाँकि, हाल ही में, कैंसर उनके शरीर में फिर से फैलने लगा। आखिरकार, शनिवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रिया मराठे इस बीच कैंसर से भी उबर चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने विदेश में एक नाटक का दौरा किया था। हालाँकि, पिछले कुछ महीनों में, कैंसर ने फिर से सिर उठा लिया था। पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। हालाँकि, उनका शरीर इलाज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। दुर्भाग्य से, शनिवार सुबह उनका निधन हो गया।

प्रिया मराठे का जन्म 23 अप्रैल 1987 को ठाणे, महाराष्ट्र में हुआ था। वह 38 वर्ष की थीं। उनका पालन-पोषण मराठी संस्कृति वाले परिवार में हुआ। 11वीं कक्षा में पढ़ते समय, प्रिया को कॉलेज की नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिला और वहीं से उनके अभिनय का सफ़र शुरू हुआ। अभिनय के प्रति बढ़ते आकर्षण को उन्होंने करियर के रूप में अपनाया।

प्रिया मराठेः एक बहुमुखी और प्रिय कलाकार

प्रिया की यात्रा दो दशकों से अधिक समय तक चली, जो मराठी धारावाहिकों से शुरू हुई और हिंदी टीवी में प्रभावशाली भूमिकाओं तक चली गई। उनकी यादगार प्रस्तुतियों में शामिल हैंः

बता दें, उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत मराठी श्रृंखला 'या सुखानो या' से की थी, जो 2007 में ज़ी मराठी पर प्रसारित हुई थी। उन्होंने चार दिवस सासुचे, या सुखानो या और हाल ही में तुज़ेच मि गीत गात आहे जैसी हिट फिल्मों में भी अभिनय किया।

विद्या बाली के रूप में 'कसम से' में उनके प्रदर्शन ने हिंदी टेलीविजन में उनके प्रवेश को चिह्नित किया। 'कॉमेडी सर्कस' में भाग लेने के अलावा, उन्होंने 'तू तीथे में' (खिलाड़ी प्रिया मोहिते के रूप में) और 'बड़े अच्छे लगते हैं' (ज्योति मल्होत्रा के रूप में) जैसे धारावाहिकों में अभिनय करके अपनी हास्य प्रतिभा का परिचय दिया।

प्रिया का विवाह अभिनेता शांतनु मोघे से हुआ था, जो स्वराज्यरक्षक संभाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। इस जोड़े ने पर्दे पर और पर्दे के पीछे, दोनों जगह एक खूबसूरत सफर साझा किया।

गलवान घाटी के शहीदों को भूली सरकार, अमेरिकी दबाव में झुके मोदी? भारत-चीन की नयी दोस्ती पर उठाए कांग्रेस ने सवाल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दुनिया के दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश - जिनके पास दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य शक्तियाँ हैं - अपनी लंबी और विवादित ऊँचाई वाली सीमा पर हफ़्तों से आमने-सामने थे। 5 मई 2020 से शुरू होकर, चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विवादित पैंगोंग झील के पास और सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा के पास, चीन-भारत सीमा पर कई स्थानों पर आक्रामक हाथापाई, आमना-सामना और झड़पें हुईं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी कई स्थानों पर झड़पें हुईं।

मई के अंत में, चीनी सेना ने गलवान नदी घाटी में भारतीय सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई। भारतीय सूत्रों के अनुसार, 15-16 जून 2020 को हुई हाथापाई में चीनी और भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि दोनों पक्षों के सैनिकों को बंदी बना लिया गया और अगले कुछ दिनों में रिहा कर दिया गया, जबकि दोनों पक्षों के आधिकारिक सूत्रों ने इससे इनकार किया। 7 सितंबर को, 45 वर्षों में पहली बार, एलएसी पर गोलियां चलाई गईं, दोनों पक्षों ने गोलीबारी के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया। भारतीय मीडिया ने यह भी बताया कि भारतीय सैनिकों ने 30 अगस्त को पीएलए पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं।

अब लगभग 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त को तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह 2020 के गलवान संघर्ष के बाद उनकी पहली चीन यात्रा है, 2020-2021 चीन-भारत झड़पों ने द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से तनावपूर्ण बना दिया था। इस मुलाकात को दो एशियाई दिग्गजों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो कभी बातचीत तो कभी टकराव के बीच उलझे रहे हैं। अब शी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आने का निमंत्रण दिया है। शी जिनपिंग ने निमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और नई दिल्ली को इसकी अध्यक्षता के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। विदेश मंत्रालय ने रविवार को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी।

आगामी वार्ता को लेकर एक अहम सवाल यह है- क्या तियानजिन में कोई नया आयाम

जुड़ सकता है? यह मुलाकात मोदी-शी संबंधों के जटिल इतिहास को दर्शाती है, जिसमें सभ्यतागत जुड़ाव से लेकर सैन्य टकराव तक शामिल है, क्योंकि दोनों देश आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रहे हैं। क्या मोदी सरकार गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है वह भूल गयी है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच रविवार को मुलाकात के बाद कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या ''न्यू नॉर्मल'' (नयी सामान्य स्थिति) चीन की आक्रामकता और ''सरकार की कायरता'' से परिभाषित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का चीन के साथ सुलह पर जोर देना वास्तव में उसकी क्षेत्रीय आक्रामकता को वैध ठहरा रहा है। मोदी ने तियानजिन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपनी बैठक में कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई मुलाकात का आकलन निम्नलिखित संदर्भों में किया जाना चाहिए- जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी आक्रामकता के चलते हमारे 20 सबसे बहादुर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इसके बावजूद, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कायराना तरीके से (कुख्यात) क्लीन चिट दे दी।'' उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर यथास्थिति की पूर्ण बहाली की मांग की थी। रमेश ने कहा, ''लेकिन इसे हासिल करने में विफल रहने के बावजूद मोदी सरकार ने चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ाए जिससे चीन की उस क्षेत्र में आक्रामकता को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता मिल गई।''

उन्होंने कहा कि चार जुलाई, 2025 को उप-सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन की 'जुगलबंदी' पर जोरदार और स्पष्ट रूप से बात की थी। रमेश ने कहा, ''मगर इस अशुभ गठजोड़ पर ठोस प्रतिक्रिया देने के बजाय मोदी सरकार ने इसे नियति मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया और अब चीन को राजकीय दौरों से पुरस्कृत कर रही है।'' उन्होंने कहा कि चीन ने यारलुंग त्संगपो पर एक विशाल जलविद्युत परियोजना की घोषणा की है जिसके ''हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेंगे लेकिन मोदी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला गया।'' रमेश ने दावा किया कि चीन से आयात की अनियंत्रित 'डंपिंग' जारी है, जिसने हमारी एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम) इकाइयों को बुरी तरह प्रभावित किया है। 'डंपिंग' का अर्थ होता है कि निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर दूसरे देश को निर्यात करना जिससे उस देश को नुकसान होता है।

चीनी सामान से बढ़ा देश का आर्थिक संकट, भाजपा की आत्मनिर्भरता खोखली, अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा प्रहार करते हुए रविवार को कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है, जिसका बुरा असर हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों के घटते कारोबार पर पड़ रहा है। सपा प्रमुख यादव ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''यही है तथाकथित आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच।''

उन्होंने इसे विस्तार से समझाते हुए कहा, ''चीन से आने वाले सामानों पर जिस तरह भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसका बुरा असर हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों के लगातार घटते जा रहे काम-कारोबार पर पड़ा है। इससे बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ रही

है।'' यादव ने आगाह करते हुए कहा, ''भाजपा चीनी चाल की क्रोनोलॉजी समझे।'' उन्होंने आगे कहा, ''पहले चीन अपना माल भारत के बाजारों में भर देगा जिससे चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने के लिए भाजपाई मजबूर हो जाएंगे।''

यादव ने दावा किया, ''उसके बाद चीन हमारे उत्पादों और उद्योगों को धीरे-धीरे बंद करवाने के कगार तक ले जाएगा और उसके बाद मनमाने दाम पर हर चीज की आपूर्ति करेगा।उसके बाद महंगाई-बेरोजगारी बढ़ाएगा।'' भविष्य के खतरों को लेकर उन्होंने आगाह किया, ''जब महंगाई और बेरोजगारी ज्यादा होगी तो सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश भी बढ़ेगा और बिना बहुमत की भाजपा की सरकार और भी कमजोर होकर लड़खड़ा जाएगी।''

सपा प्रमुख ने कहा, ''फिर खुद ही लड़खड़ाती भाजपा सरकार चीन के अतिक्रमण को चुनौती नहीं दे पाएगी... उसके बाद हमारी जमीन पर चीन अपना कब्जा और बढ़ाएगा।... इसके बाद भाजपा दोहराएगी कि 'न कोईष्ठ न कोईष्ठ!'' यादव ने कहा, ''अगर ये बात 'ड्रोनवालों' को समझ नहीं आ रही है तो उत्तर प्रदेश में विराजमान 'बुलडोजर' वाले प्रवासी जी ही ये सच्चाई समझकर जवाब दें कि चीन ने हमारी कितनी जमीन हड़प ली है, क्योंकि उनका मूल निवास स्थान भी चीन के कब्जे का शिकार हुआ है।''

सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा, ''भाजपाई बस देश का क्षेत्रफल बता दें, मतलब ये बता दें कि भाजपा सरकार के आने के समय देश की कुल भूमि जितनी थी, क्या अब भी उतनी ही है

मोहम्मद अज़हरुद्दीन तेलंगाना विधान परिषद के लिए मनोनीत, कांग्रेस नेताओं का जताया आभार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अज़हरुद्दीन को तेलंगाना में राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्होंने कैबिनेट के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे 'सम्मानित और विनम्र' करने वाला क्षण बताया।

अज़हरुद्दीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इन नेताओं के विश्वास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, टीपीसीसी प्रमुख महेश गौड़ और तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन को भी उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और राज्य की 'ईमानदारी और

समर्पण' के साथ सेवा करने का वादा किया।

शनिवार, 30 अगस्त को, तेलंगाना कैबिनेट ने विधान परिषद के लिए दो नामों को मंजूरी दी, जिनमें प्रोफेसर एम. कोडंडाराम और मोहम्मद अज़हरुद्दीन शामिल हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें तेलंगाना जन समिति के संस्थापक कोडंडाराम और द सियासत डेली के समाचार संपादक आमेर अली खान के पिछले नामांकन रद्द कर दिए गए थे।

इन नामांकनों को भारत राष्ट्र समिति के नेताओं दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण ने कानूनी चुनौती दी थी। उनकी सिफारिशों को 2023 में तत्कालीन राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने उनकी राजनीतिक संबद्धता के कारण खारिज कर दिया था। मार्च 2024 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया था, और साथ ही कोडंडाराम और खान को नामित करने के कैबिनेट के फैसले को भी अमान्य घोषित कर दिया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दोनों को शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए थी। अज़हरुद्दीन का नामांकन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए उन्हें पहले कांग्रेस का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। अज़हरुद्दीन ने 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

पीएम मोदी का शी जिनपिंग को ब्रिक्स न्योता! सीमा विवाद के समाधान पर जोर, कहा- भारत-चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं, विकास भागीदार

बीजिंग **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसकी मेजबानी भारत 2026 में करेगा। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए चीन में हैं और रविवार को उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन की पेशकश की।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शी ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत और चीन 'प्रतिद्वंद्वी' नहीं, बल्कि 'विकास साझेदार' हैं और उनके बीच मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। उन्होंने भारत और चीन के बीच स्थिर संबंधों पर भी ज़ोर दिया और कहा कि यह दोनों देशों के विकास और बहुध्रुवीय विश्व के लिए आवश्यक है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी के साथ बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के महत्व पर भी ज़ोर दिया। इसमें कहा गया है कि दोनों नेता पिछले साल पूर्वी लद्दाख

से सैनिकों की सफल वापसी से संतुष्ट थे।

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'उन्होंने अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के लोगों के दीर्घकालिक हितों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में दोनों विशेष प्रतिनिधियों द्वारा अपनी वार्ता में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को मान्यता दी और उनके प्रयासों को आगे भी समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की।'

दोनों नेताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सीधी उड़ानों और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी आगाह किया कि भारत-चीन संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों, जैसे आतंकवाद और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार, पर साझा आधार का विस्तार करना आवश्यक समझा।' साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की चीन की अध्यक्षता के लिए समर्थन व्यक्त किया।

बाद में, प्रधानमंत्री मोदी ने कैक्यूई से भी मुलाकात की, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की सदस्य हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने श्री कैई के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया और दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उनका समर्थन माँगा। श्री कैई ने दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप द्विपक्षीय आदान-प्रदान का विस्तार करने और संबंधों को और बेहतर बनाने की चीनी पक्ष की इच्छा दोहराई।'

वैश्विक बदलावों के बीच शी जिनपिंग का संदेश- भारत-चीन मिलकर गढ़ें बहुध्रुवीय विश्व का नया अध्याय

बीजिंग **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत-चीन संबंधों का मार्गदर्शन आपसी विश्वास और सम्मान से होना चाहिए। इस द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत दोनों नेताओं के बीच हाथ मिलाने से हुई, जो दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वियों के बीच सुलह की दिशा में अगले कदम का संकेत था। साथ ही, यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक संदेश था, जिनके टैरिफ संबंधी आक्रामक रुख ने नई दिल्ली और बीजिंग, दोनों के साथ वाशिंगटन के संबंधों को खराब कर दिया है।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से रविवार को कहा कि दोनों देशों का ''मित्र'' बनना ''सही विकल्प'' है तथा ''हाथी (भारत) एवं ड्रैगन (चीन)'' को एक-दूसरे की सफलता का मिलकर जश्न मनाना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर हुई। शी ने कहा, ''हम दोनों (देशों) के कंधों पर अपने लोगों के भले के लिए काम करने, विकासशील

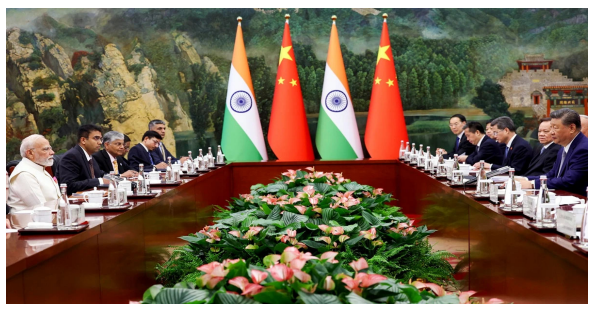

देशों का कायाकल्प करने एवं उनकी एकजुटता को बढ़ावा देने और मानव समाज की प्रगति को गति देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है।''

उन्होंने कहा, ''दोनों के लिए यह सही विकल्प है कि वे ऐसे दोस्त बनें जिनके बीच अच्छे पड़ोसियों वाले और सौहार्दपूर्ण संबंध हों, वे ऐसे साझेदार बनें जो एक-दूसरे की सफलता में सहायक हों और 'ड्रैगन' और हाथी एक साथ नृत्य करें।'' चिनफिंग ने मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और चीन को अपने संबंधों को ''रणनीतिक'' और ''दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य'' से देखना चाहिए।

शी ने कहा, ''दोनों पक्षों को अपने संबंधों को रणनीतिक ऊंचाइयों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना एवं संभालना होगा ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों का निरंतर, मजबूत और स्थिर विकास हो सके।'' चीन की सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की खबर के अनुसार, शी ने मोदी से कहा कि चीन और भारत प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहयोगी हैं तथा दोनों देश एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर हैं।

उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा नीतियों पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए कहा कि दोनों देशों को बहुपक्षवाद को बनाए रखना चाहिए। शी ने कहा कि भारत और चीन को एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था बनाने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''हमें बहुपक्षवाद को बनाए रखने, एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए मिलकर काम करने और एशिया एवं दुनिया भर में शांति और समृद्धि में उचित योगदान देने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को भी आगे बढ़ाना होगा।''

सितंबर में फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने के मैक्रों के फैसले से इजराइल एवं अमेरिका नाराज

यरुशलम **(एजेंसी)**। फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निर्णय के बाद अन्य पश्चिमी देशों ने भी इसी प्रकार के कदम उठाए जिसे लेकर इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका में नाराजगी है। इस फैसले ने गाजा में जारी विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों के केंद्र में दो-राष्ट्र समाधान को एक बार फिर से ला खड़ा किया। पिछले सप्ताह इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लिखे एक पत्र में राष्ट्रपति मैक्रों ने लिखा, 'फलस्तीनी जनता को उनका अपना राष्ट्र दिलाने के हमारे संकल्प की जड़ें इस विश्वास से जुड़ी हैं कि स्थायी शांति इजराइल की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।'

मैक्रों ने कहा, 'फ्रांस के कूटनीतिक प्रयास गाजा में उस भयावह मानवीय आपदा पर हमारे आक्रोश से उत्पन्न हुए हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं हो सकता।' इजराइल ने शुक्रवार को गाजा के सबसे बड़े शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सात अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हमले के साथ शुरू हुए युद्ध में अब तक 63, 000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं।

फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा ने कहा है कि वे 23 सितंबर से शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के दौरान फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के अपने संकल्प को औपचारिक रूप देंगे। न्यूजीलैंड, फिनलैंड और पुर्तगाल सहित कुछ अन्य देश भी इसी तरह के कदम पर विचार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने फलस्तीनी राष्ट्र का दर्जा अस्वीकार कर दिया है और वह गाजा में सैन्य अभियान बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने से चरमपंथियों का हौसला बढ़ता है।

एससीओ बैठक में मोदी अग्रणी, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता कद

बीजिंग **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में ग्रुप फोटो में सबसे आगे खड़े थे। इस फोटो में उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे, जिन्होंने इस मीटिंग की मेजबानी की थी।

इस मीटिंग में दुनिया भर के बड़े नेता आए थे। शी जिनपिंग ने अपनी पत्नी पेंग लियुआन के साथ तियानजिन शहर में एक डिनर भी रखा था।

इस ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शी जिनपिंग, पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी शामिल थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ भी इस फोटो में आगे की लाइन में खड़े थे।

प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह आगे खड़े होना दिखाता है कि दुनिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और एससीओ जैसी संस्थाओं में उसकी भूमिका बहुत खास है। यह मीटिंग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इसमें शामिल देशों की आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी कई बातें एक जैसी हैं।

किसी के निर्देश पर नहीं चलेंगे, रूस से तेल खरीद पर पीटर नवारो को पूर्व राजनयिक ने दिया करारा जवाब

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। भारत के पूर्व विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की टिप्पणियों के संदर्भ में यह चेतावनी दी है कि ट्रंप प्रशासन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

नवारो ने हाल ही में भारत के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने भारत को 'शुल्कों का महाराजा' कहा और रूस से तेल खरीदने के लिए उसकी आलोचना की है। इस पर, विकास स्वरूप ने करारा जवाब दिया कि भारत ने हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत का पालन किया है और किसी के 'निर्देश' पर नहीं चलेगा।

एक समाचार एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में, स्वरूप ने कहा, 'मौजूदा संबंध अच्छे नहीं हैं। हम सभी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो व्यक्तिगत संबंध विकसित हुए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं, उसे देखते हुए, हमें लगा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी अधिकारी भारत पर हर तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत एक बहुत ही गौरवान्वित राष्ट्र है। भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत का पालन किया है। हम किसी के निर्देश पर नहीं चलेंगे।'

स्वरूप ने दोनों देशों के बीच प्रगति की उम्मीद जताते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने का समय अभी भी बाकी है।' हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि 'निश्चित रूप से, ट्रंप प्रशासन, खासकर पीटर नवारो की ओर से आ रही वर्तमान टिप्पणियां, इस मामले में कोई मदद नहीं कर रही हैं।'

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)